▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठ: 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

फाल्गुन–चैत्र 2076–77, मार्च 2020

मोदी, ट्रंप और भारत–अमरीका संबंध

स्वदेशी गतिविधियां

प्रांत सम्मेलन, गुजराज

सचित्र झलकियां

स्वदेशी संकल्प परिवार सम्मेलन, जमशेदपुर (झारखंड)

विचार वलय, जोधपुर (राजस्थान)

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–28, अंक–3
फाल्गुन–चैत्र 2076–77 मार्च 2020

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 33-37

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

सफल विदेश नीति की दास्तां है मोदी–ट्रंप की दोस्ती
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा-2
मोदी, ट्रंप और भारत अमरीका संबंध ..... विक्रम उपाध्याय

11 ज्वलंत मुद्दा
भारतीय आर्थिकी के अनुकूल नहीं है आभासी मुद्रा ..... स्वदेशी संवाद

13 कृषि
किसान जस के तसः बीमा कंपनियों की चांदी ..... अनिल तिवारी

15 आजकल
कोरोना वायरस एक वैश्विक चुनौती ..... वैदेही

17 विश्लेषण
अभी भी चौराहे पर है अफगानिस्तान का भविष्य ..... दुलीचन्द कालीरमन

19 आर्थिकी
कैसे कमाती है लाभ सार्वजनिक इकाइयां ..... भरत झुनझुनवाला

21 खोज-खबर
यस बैंक संकटः सबक सीखने की दरकार ..... स्वदेशी संवाद

23 समीक्षा
उ.प्र. का बजट (2020–21): युवाओं, किसानों व गरीबों पर केंद्रित ..... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

25 जल प्रबंधन
बांधों न बांध हर ठांव बंधु! ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

28 पर्यावरण
भारतीय वाङ्मय में पर्यावरण शिक्षा ..... डॉ. विजय वशिष्ठ

31 जन्मशताब्दी
आर्थिक स्वतंत्रता के लिये जन–जागरण का आह्वानः दत्तोपंत ढेंगड़ी ..... डॉ. रेखा भट्ट

पाठकनामा

रणनीतिक निजीकरण देशहित में नहीं

लाभकारी सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण किये जाने की जगह सरकार को वैकल्पिक रास्तों की तलाश करनी चाहिए। जीएसटी और विमुद्रीकरण के बाद खजाने की कड़की से जूझ रही केंद्र सरकार को आने वाले वर्षों में तकरीबन 5 लाख करोड़ रूपये की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए सरकार को कीनेसियन अर्थशास्त्रियों से सलाह मशविरा कर व्यापक संदर्भ में अल्पकालीन और दीर्घकालीन रणनीति बनानी चाहिए।

1950 में स्थापित बीपीएल भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी हैं, जिसमें 12,157 कर्मचारी हैं। सरकार इसकी संपूर्ण 52.98 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी खुले बाजार में बेचेगी। यानि कि यह सरकारी से प्राइवेट हो जायेगी। बीपीएल का कुल सेल टर्नओवर 2018–19 में 337,622.53 करोड़ रूपये हैं। कंपनी का लाभ पीबीडीआईटी 14,809.84 करोड़ है, जो कि पिछले पांच वर्षों से उठापटक के बाद भी लगातार बढ़ रहा हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 87,388 करोड़ रुपये है और मौजूदा कीमतों पर सरकार की हिस्सेदारी लगभग 46,000 करोड़ रुपये है। इतनी कम कीमत पर इसे बेचना अतार्किक हैं, घाटे को सौदा है। इस बीच कई एक संगठनों ने दावा किया कि बीपीसीएल को बेचने से नुकसान होगा, क्योंकि इसकी कीमत 9.75 ट्रिलियन है, जबकि सरकारी स्वामित्व 52.98 प्रतिशत है।

मालूम हो कि आज की तारीख में दुनिया की तमाम बड़ी तेल कपंनियां सऊदी अरामको, सिनोपेक समूह चीन, राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम चीन, कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कुवैत आदि सभी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं और इनका डंका दुनिया में बजता हैं। बीपीसीएल भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक तेल कंपनी हैं। सरकार ने बजट में 2 लाख करोड़ रुपए का सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियों के विनिवेश तथा साथ ही 49 प्रतिशत के कम हिस्सेदारी का प्रस्ताव किया है। अर्थात प्रबंधन नियंत्रण भी निजी हाथों में सौपने की योजना है। तेल और रिफाईनरी जैसे अतिआवश्यक और रणनीतिक क्षेत्र के निजीकरण प्रस्ताव से बाजार में शोषण और अस्थिरता पैदा होगी, जिसका दुष्परिणाम आम जनता का भुगतना पड़ेगा। वैसे भी विनिवेश का इतिहास विवादास्पद रहा हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बाल्को के विनिवेश में, जिसके शेयर 1000 रुपये के आसपास थे, विनिवेश के लिए शेयरों का मूल्यांकन 77 रुपये पर किया गया, जिससे 9,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। उस विनिवेश की फाइल के पेपर आज तक नही मिले।

ऐसे में हमें कोल इंडिया लिमिटेड से सबक लेना चाइए, जिसे कोई खरीदना वाला नहीं था और समय आने पर शेयर बाजार में लिस्टिंग किया और रिकार्ड 100000 करोड़ से ज्यादा पैसा बाजार से मिला। बाद में कोल इंडिया का नाम 'काला सोना' के रूप में दर्जा किया गया।

*–**सोहनलाल गोसाई,** एसोसिएट प्रोफेसर, राजस्थान*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

हमें याद रखना चाहिए कि वैज्ञानिक अनुसंधान के फल का सबसे अच्छा प्रभाव तब होगा जब वे हमारे कम-विशेषाधिकार प्राप्त संस्थानों, हमारे युवाओं, हमारी महिलाओं और हमारे सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचेंगे।

रामनाथ कोविन्द (राष्ट्रपति, भारत)

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान प्रस्तुत करते समय दिए गए अपने भाषणों में रेखांकित किया था, 'अब हमारे देश के लिए जो कुछ भी होगा उसके लिए हम अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहरा सकते। देश के लिए जो भी होगा उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। हमें अब सावधान रहना होगा और सावधानी से चलना होगा'।

डॉ. मोहन भागवत (सरसंघचालक, संघ)

भारत की जैव विविधता संपूर्ण मानव जाति के लिए एक 'अद्वितीय खजाना' है।

नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री, भारत)

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब अमेरिका अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए भारत पर दबाव बना रहा है, भारत की पहली प्राथमिकता अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य, छोटे व्यवसायों और उद्योगों में रोजगार की रक्षा करना है।

स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

बचत संस्कृति पर आघात

वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2020–21 के बजट में नई वैकल्पिक वैयक्तिक आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है, जिसमें नए विकल्प में आयकर की दरों को घटाया गया है, लेकिन इस विकल्प के साथ शर्त यह है कि करदाताओं को इससे पहले मिलने वाली कटौतियों और छूट का त्याग करना होगा। वैयक्तिक आयकर की प्रस्तावित दरें 2.5 लाख से 5 लाख रूपए तक की आय के बीच 5 प्रतिशत, 5 लाख 7.5 लाख रूपए की बीच की आय पर 10 प्रतिशत, 7.5 लाख से 10 लाख रूपए के बीच की आय पर 15 प्रतिशत, 10 लाख से 12.5 लाख रूपए के बीच की आय पर 20 प्रतिशत, 12.5 लाख से 15 लाख रूपए के बीच की आय पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रूपए से अधिक सभी आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा। इन आयकर करों के अतिरिक्त लागू उपकर (सेस) भी लगेंगे।

गौरतलब है इससे पहले केवल एक ही विकल्प उपलब्ध था, जिसके अनुसार विभिन्न छूटों के साथ 2.5 लाख से 5 लाख रूपए के बीच की आय पर आयकर 5 प्रतिशत था, जबकि 5 लाख से 10 लाख रूपए के बीच की आय पर यह आयकर 20 प्रतिशत और 10 लाख रूपए और उससे अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रावधान था। नई वैकल्पिक व्यवस्था में आयकर की दरों को इस प्रकार से रखा गया है कि वेतनभोगी आयकर दाता जो आमतौर पर सालाना 1.5 लाख रूपए की बचत कर रहे हैं और 50 हजार रूपए की मानक कटौती का लाभ उठा रहे हैं और किसी अन्य रियायत अथवा छूट का लाभ नहीं ले रहे, वे पूर्व के मुकाबले कम कर का भुगतान करेंगे और उन्हें कोई बचत भी नहीं करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए 20 लाख रूपए की आय वाले वेतनभोगी आयकर दाताओं को नए व्यवस्था के तहत केवल 3,37,500 रूपए का आयकर देना होगा, जबकि इससे पूर्व वे निर्दिष्ट स्कीमों में निवेश के रूप में बचत की छूट का लाभ उठाने के बाद भी 3,45,000 रूपए का भुगतान करते थे।

सरकार का दावा है कि 80 प्रतिशत करदाता नए विकल्प के साथ चले जाएंगे, और यह दावा शायद सही भी है क्योंकि नए विकल्प के साथ जाना ही अधिकांश करदाताओं के लिए फायदेमंद होगा। इस प्रकार से नई या वैकल्पिक कर व्यवस्था को आयकर दाताओं के लिए एक राहत के रूप में चित्रित किया जा सकता है। लेकिन हमें समझना होगा कि नए प्रस्तावों में जहां आयकर दाताओं को आयकर से राहत दी जा रही है, लेकिन यह प्रस्ताव बचत संस्कृति, अर्थव्यवस्था में समग्र बचत और अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।

यह सर्वविदित ही है कि भारतीयों में बचत की प्रवृत्ति काफी प्रबल है। आमतौर पर लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने हेतु अचल संपत्ति और सोने की खरीद के साथ–साथ अपने भविष्य की जरूरतों जैसे, संतानों के विवाह और उनके भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचत करते हैं। पिछले कई दशकों से सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की रियायतें देकर विशिष्ट प्रकार की बचतों को प्रोत्साहित किया जाता रहा है, जैसे, जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि एवं सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) इत्यादि। इन बचतों के अलावा पिछले कुछ सालों से सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में 50 हजार रूपए तक के सालाना के अंशदान पर भी आयकर में छूट दे रही है। इन उपायों से देश में बचत तो बढ़ती ही है, इनसे सरकार अपने राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु उधार तो लेती ही है, इन संसाधनों से हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर और पूंजी निवेश के निर्माण में भी काफी मदद मिली है। सरकार की यह कार्यवाही देश में बचत को हतोत्साहित कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि देश में पूंजी निर्माण की दर समय के साथ–साथ बढ़ती रही है। वर्ष 2011–12 तक सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर जीडीपी के 39.6 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इस पूंजी निर्माण को काफी हद तक घरेलू बचत द्वारा ही वित्त पोषित किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2007–08 तक घरेलू पूंजी निर्माण में विदेशी संसाधनों का योगदान कभी भी जीडीपी के 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहा। हाल ही में कुछ सालों में यह जीडीपी के 4 से 5 प्रतिशत तक रहा। लेकिन औसतन यह 2 प्रतिशत से कम ही रहा। 2011–12 के बाद सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर घटती गई और 2017–18 में यह मात्र 30.9 प्रतिशत ही रह गई। पूंजी निर्माण की दर घटने का प्रमुख कारण यह रहा कि देश में गृहस्थ क्षेत्र की बचत 2011–12 में जीडीपी के 23.6 प्रतिशत से घटती हुई 2017–18 में मात्र 17. 2 प्रतिशत रह गई। गृहस्थ क्षेत्र में बचत की प्रवृत्ति पिछले दशक में काफी कम हुई है, जिसके कारण पूंजी निर्माण की दर भी घटती जा रही है। जीडीपी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए देश में पूंजी निर्माण बढ़ाना जरूरी है और पूंजी निर्माण बढ़ाने के लिए घरेलू बचत को बढ़ाना जरूरी है।

यदि आयकर दाता वैकल्पिक कर प्रणाली अपनाते हैं तो उसका सीधा असर सरकारी खजाने पर भी पड़ सकता है और सरकार का राजस्व कम हो सकता है। इसके अलावा नहीं भूलना चाहिए कि सरकार के राजकोषीय घाटे की भरपाई वित्तीय संस्थानों और फंडों (बीमा कंपनियों, भविष्यनिधी, पेंशन फंड आदि) से उधार लेकर की जाती रही है। लेकिन इन प्रतिभूतियों में घरेलू बचत कम होने के कारण सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के स्रोत सिकुड़ जाएंगे और सरकार को अपना घाटा पूरा करने के लिए अतिरिक्त नोट छापने होंगे, जो मुद्रास्फीति कारक होगा।

सफल विदेश नीति की दास्तां है मोदी-ट्रंप की दोस्ती

शांति और सौहार्द बढ़ने के आसार

अपनी 36 घंटे की भारत यात्रा पूर्ण कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापिस लौट चुके हैं। पिछले लगभग एक माह से डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। आज की दुनिया में विभिन्न मुल्कों के साथ राजनयिक, सामरिक एवं आर्थिक संबंधों की एक विशेष भूमिका है। ऐसे में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमरीका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, आज के समय की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। इस यात्रा का महत्व और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हाल ही में भारत की संसद ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर आजादी के समय से चल रहे एक महत्वपूर्ण विवाद की जड़, धारा 370 को समाप्त कर दिया। पाकिस्तान, कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के रास्ते विभिन्न प्रकार से लगातार कश्मीर को भारत से अलग करने की नापाक कोशिशें करता रहा है। कश्मीर को एक विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 की समाप्ति से कश्मीर में शांति का मार्ग खुला, लेकिन इसको स्थाई रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाया जाना भी जरूरी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर कि भारत कश्मीर के लिए जो भी करेगा अच्छा ही होगा, कश्मीर के मुद्दे पर विवादों पर लगभग पूर्ण विराम लगा दिया है।

भारत यात्रा से पहले और उसके दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बार–बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपनी मित्रता का हवाला भी दिया। समझा जा सकता है कि दुनिया के दो महान राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों के बीच इस प्रकार का सौहार्द एक अच्छा संकेत है। पिछले लंबे समय से अमरीका, चीन और भारत के साथ व्यापार युद्ध छेड़े हुए हैं। चीन के साथ अमरीकी राष्ट्रपति की यह शिकायत है कि वह अपने सस्ते माल को अमरीका में डंप करते हुए अमरीकियों के रोजगार को समाप्त कर रहा है। इसलिए अपने देश के रोजगार और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वे हर कदम उठाएंगे। इसके साथ ही साथ अमरीका को भारत से भी यह शिकायत है कि भारत तमाम प्रकार का सामान अमरीका में बेचता है, लेकिन अमरीकी सामान पर बहुत ऊंचे आयात शुल्क लगाएं जाते हैं या उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। पिछले काफी समय से अमरीका, चीन और भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ यानि आयात शुल्क लगातार बढ़ाता जा रहा है। कुछ माह पूर्व अमरीका ने भारत को रियायत देने वाला एक प्रावधान 'जीएसपी' हटा दिया था, जिससे भारत से जाने वाले लगभग 5.6 अरब डालर के निर्यातों पर असर पड़ा। ट्रंप की भारत यात्रा से कुछ दिन पहले ही अमरीका ने भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से हटाकर विकसित देशों की श्रेणी में डाल दिया था। इसका असर यह होगा कि भारत को विकासशील देश के रूप में मिलने वाली व्यापार रियायतें समाप्त हो जाएंगी।

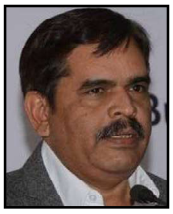

डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर कि भारत कश्मीर के लिए जो भी करेगा अच्छा ही होगा, कश्मीर के मुद्दे पर विवादों पर लगभग पूर्ण विराम लगा दिया है।
– डॉ. अश्वनी महाजन

अमरीका को भारत से केवल यही शिकायत नहीं है कि वह अमरीका से आने वाले सामान पर भारी शुल्क लगाता है, बल्कि यह शिकायत भी है कि उसने अमरीका के दुग्ध उत्पादों के

आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। साथ ही साथ अमरीकी कंपनियों की यह भी शिकायत है कि भारत ने हृदय में लगने वाले स्टंट, कृत्रिम घुटने समेत स्वास्थ्य उपकरणों पर कीमत नियंत्रण लागू किए हुए हैं, जिसके कारण वे मुश्किल में हैं। उधर भारत ने पिछले कुछ समय से अमरीकी ई–कॉमर्स कंपनियों पर विभिन्न प्रकार के अंकुश लगाए हैं। अमरीका की यह भी शिकायत है कि भारत का पेटेंट कानून उनकी कंपनियों के हितों के विपरीत है।

भारत ने अमरीका को दो टूक यह समझाया है कि हम उनकी मांगों को नहीं मान सकतें क्योंकि जहां डेयरी का सवाल है, यह मुद्दा गरीब किसानों की जीविका से तो जुड़ा हुआ है ही, अमरीका का दूध मांसाहारी गायों से प्राप्त होता है, जो हमारे सांस्कृतिक संवेदनाओं को आहत करने वाला है। अमरीकी ई–कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनाप–शनाप डिस्काउंट देने के कारण भारत के छोटे दुकानदार अपनी जीविका खो रहे हैं, इसलिए इन कंपनियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। जहां तक पेटेंट समेत हमारा बौद्धिक संपदा कानून है यह हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा और किसानों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इसे किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। यही नहीं आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कीमतों पर नियंत्रण देश में गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नितांत जरूरी है।

शिकायतों की भरमार के बीच अमरीका को ऐसा लगता था कि जैसे पूर्व में वे आर्थिक प्रतिबंधों का डर दिखाकर या अन्य प्रकार के दबाव डालकर अपनी बातें मनवा लेते थे, इस बार भी वे भारत को दबाव में लेकर कोई ऐसा व्यापार समझौता कर पाएंगे, जिससे अमरीका के हितों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन ट्रंप की यात्रा से कुछ दिन पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि भारत और अमरीका के बीच एक सीमित व्यापार समझौता भी नहीं हो पाएगा।

अमरीका को नहीं भूलना चाहिए कि भारत आज दुनिया की उभरती महाशक्ति है, जिसकी मजबूती वैश्विक सामरिक संतुलन के लिए भी बहुत जरूरी है। अपने छोटे–मोटे आर्थिक हितों का परित्याग करते हुए उसे भारत की भावनाओं का आदर करना चाहिए।

ट्रंप ने भारत आने से पहले ही यह घोषणा भी कर दी थी कि भारत उनकी बातें नहीं मान रहा, जिसके कारण व्यापार समझौता तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद वे भारत आएंगे क्योंकि मोदी उन्हें अच्छे लगते हैं। ट्रंप की यात्रा के अंत में भारत और अमरीका ने आगे चलकर एक वृहद व्यापार समझौते की बात कही है, लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि भारत अपने हितों से किसी भी हालत में समझौता नहीं करेगा।

अमरीका को नहीं भूलना चाहिए कि भारत उसके लिए एक महत्वपूर्ण बाजार भी है। भारत का लगातार विकसित होता नागरिक उड्डयन उद्योग अमरीका की बोईंग कंपनी के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है और अगले कुछ वर्षों में भारत अमरीका की बोईंग कंपनी से 40 अरब डालर की लागत के 300 बोईंग विमान खरीदने वाला है। आज अमरीका भारत को तेल निर्यात करने वाला बहुत महत्वपूर्ण देश बन चुका है। ऐसे में अमरीका जिस व्यापार घाटे को लेकर शिकायत कर रहा है, वह अगले कुछ सालों में समाप्त ही होने वाला है।

अमरीका को समझना होगा कि भारत और अमरीका के बीच अच्छे संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बनाने के लिए नितांत जरूरी है। इसी कारण भारत–अमरीका संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में यह बात स्पष्ट हो रही है कि दोनों देश प्रतिरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। भारत और अमरीका के बीच सामरिक सहकार बढ़ने से इस महाद्वीप में शक्ति संतुलन बेहतर हो सकेगा और चीन जो लगातार अपनी सामरिक उपस्थिति इस क्षेत्र में बढ़ा रहा है, उसको भी उचित जवाब मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से चीन 'बेल्ट रोड परियोजना' के तहत विभिन्न देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन्हें कर्ज के जाल में डुबोता जा रहा है। इसके माध्यम से वह उन मुल्कों के सामरिक महत्व की परिसंपत्तियों पर कब्जा कर इस क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बना हुआ है। भारत और अमरीका के बीच सामरिक सहभाग चीन को एक उचित जवाब माना जा सकता है।

अमरीका की अनुचित व्यापार एवं आर्थिक मांगों को दृढ़ता से मना करते हुए व्यापार समझौता न करने और भारत–अमरीकी संबंधों में इस विवाद को आड़े न आने देते हुए, अमरीका को कश्मीर के मुद्दे पर अपने पक्ष में लेना, सामरिक समझौते करना आदि नरेन्द्र मोदी सरकार के अंतर्गत भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है। ट्रंप ने बार–बार यह कहा भी है कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे मित्र हैं, लेकिन उतने ही कठोर वार्ताकार भी।

अमरीका को नहीं भूलना चाहिए कि भारत आज दुनिया की उभरती महाशक्ति है, जिसकी मजबूती वैश्विक सामरिक संतुलन के लिए भी बहुत जरूरी है। अपने छोटे–मोटे आर्थिक हितों का परित्याग करते हुए उसे भारत की भावनाओं का आदर करना चाहिए। अमरीका इतिहास में पाकिस्तान का समर्थक रहा है। ऐसे में अमरीका की भारत के साथ बढ़ती नजदीकियां इस क्षेत्र में भारत की विदेश नीति की सफलता तो है ही, इस क्षेत्र में शांति और सौहार्द के लिए अच्छा संकेत भी है। ❑❑

मोदी, ट्रंप और भारत अमरीका संबंध

अमरीकी राष्ट्रपति का भारत आना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख से नहीं जुड़ा था, बल्कि भारत के आन–बान–शान से भी जुड़ा था। यह बात देश के दुश्मनों को भी मालूम थी और यहां घरेलू स्तर पर विपक्षी नेताओं को भी। भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़ी ताकतों ने भरपूर कोशिश की कि राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे से भारत को मिलने वाली ख्याति या लाभ को रोका जाए या उसे दूसरे प्रोपोगांडा के जरिए मलिन कर दिया जाए। कुछ हद तक यह प्रयास सफल भी हुआ। जिस राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय मीडिया को राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी की मुलाकात का विश्लेषण करना था वह मीडिया दिल्ली, सीएए, मुस्लिम विरोधी दंगे और मोदी सरकार की 'नाकामी' का विश्लेषण कर रहा है। पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में अमरीकी राष्ट्रपति से अपनी दोस्ती और गाढ़ी करने और भारत के पक्ष में इस दौरे को मोडने जो सफलता प्राप्त की वह सुनहरे अक्षरों में अंकित किया जाएगा।

राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच दोस्ती इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। खासकर पूर्वी एशिया में। जहां एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ जारी मोर्चा और मजबूत हो सकता था, वहीं चीन से मिल रही आर्थिक और सामरिक चुनौतियों से लड़ने के लिए भी मजबूत आधार और सहयोग मिल सकता था। लेकिन ट्रंप के भारत दौरे की सफलता पर जिस तरह आंशका के कोहरे बिछाए गए उससे सफलता की ध्वनि कमजोर तो हुई ही।

राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे से सबसे बड़ा डर पाकिस्तान को था। इसलिए प्रधानमंत्री इमरान खान खुद पाकिस्तान की प्रोपोगेंडा मशीन अपने हाथों में लेकर इस दौरे को कमजोर करने में जुटे थे। सबसे पहले पाकिस्तान से यह झूठ फैलाने की कोशिश की कि एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की फरवरी में होने वाली बैठक में ट्रंप प्रशासन ने इस्लामाबाद को ग्रे सूची से निकालने का भरोसा दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरैशी

प्रधानमंत्री मोदी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में अमरीकी राष्ट्रपति से अपनी दोस्ती और गाढ़ी करने और भारत के पक्ष में इस दौरे को मोड़ने जो सफलता प्राप्त की वह सुनहरे अक्षरों में अंकित किया जाएगा।
– विक्रम उपाध्याय

ने खुद आगे बढ़कर यह दावा किया कि अफगानिस्तान में शांति प्रकिया के लिए जो सहयोग पाकिस्तान दे रहा है उसके बदले अमरीका उसे एफएटीएफ की सूची से बाहर निकालने में मदद करेगा। लेकिन हुआ उसके उल्टा।

पाकिस्तान को न सिर्फ ग्रे सूची में बरकरार रखा गया, बल्कि उसे यह चेतावनी भी दी गई कि यदि चार महीने में आतंकवादी फंडिंग को नहीं रोका गया तो पाकिस्तान को काली सूची में डाल दिया जाएगा। एफएटीएफ पर मुंहकी खाने के बाद भी पाकिस्तान राष्ट्रपति ट्रंप के भारत के दौरे को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास करता रहा। ट्रंप का यह कहना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से उनके अच्छे संबंध हैं, इसी से इस्लामाबाद को संजीवनी मिल गई। राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के बीच में ही इमरान खान ने विश्व समुदाय से यह अपील कर दी कि दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए।

यद्यपि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद का नाम लिया, लेकिन उससे पाकिस्तान को सीधे जोड़ने से बचते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान नहीं, बल्कि हमारे विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हैं, जिसने लगातार यह प्रचारित किया कि सीएए या एनआरसी मुसलमानों को डराने या उनकी नागरिकता पर संदेह जताने के लिए लाया गया है। पाकिस्तान इन्हीं चीजों को लगातार भुनाता रहा और अतंतः अपने उपर ट्रंप की किसी टिप्पणी को टालने में सफल रहा। यह प्रधानमंत्री मोदी की सफल कूटनीति है, जिसने राष्ट्रपति ट्रंप को यह सफलता पूर्वक समझाया कि ये दो कानून किसी धार्मिक समूह के खिलाफ नहीं, बल्कि देश में घुसपैठियों को चिन्हित करने और पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता देने से है। यह

ट्रंप ने विश्व बिरादरी को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में धार्मिक आजादी दुनिया के किसी भी देश से अधिक है और सीएए या एनआरसी भारत का आंतरिक मामला है।

हमारी बड़ी कूटनीतिक जीत है कि स्वयं ट्रंप ने विश्व बिरादरी को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में धार्मिक आजादी दुनिया के किसी भी देश से अधिक है और सीएए या एनआरसी भारत का आंतरिक मामला है।

प्रधानमंत्री मोदी के उद्‌गार

- यह संबंध, 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में है और इसलिए आज राष्ट्रपति ट्रंप और मैंने हमारे संबंधों को कॉम्प्रिहेन्सिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है।
- आतंक के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए आज हमने अपने प्रयासों को और बढ़ाने का निश्चय किया है।
- हमारे बीच ड्रग तस्करी, नार्को–आतंकवाद और संगठितत अपराध जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में एक नए मेकैनिज्म पर भी सहमति हुई है।
- हमारी स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप सुदृढ़ होती जा रही है। और इस क्षेत्र में आपसी निवेश बढ़ा है।
- तेल और गैस के लिए अमेरिका भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्त्रोत बन गया है। हम एक बड़ी ट्रेड डील के लिए बात करेंगे।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उद्‌गगार

- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं, मोदी एक शानदार नेता हैं।
- भारत में मेरा जैसा स्वागत किया गया, वैसा किसी का नहीं किया गया होगा। हमारे राजदूत ने भी कहा –ऐसा स्वागत कभी नहीं देखा।
- मैं आपके देश की सराहना करता हूं, पीएम की सराहना करता हूं, ये कूटनीति की दोस्ती है।
- आतंकवाद के मुद्दे पर हमने विस्तार से बात की। पीएम मोदी धार्मिक शख्स हैं, शांत हैं, लेकिन मजबूत व्यक्तित्व वाले हैं, आतंकवाद के खिलाफ वह लड़ रहे हैं।
- हमने धार्मिक स्वतंत्रता पर बात की। धार्मिक आजादी पर भारत सही काम कर रहा है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान।
- कश्मीर भारत–पाकिस्तान के बीच बड़ी समस्या है, लेकिन दोनों इस समस्या को सुलझा सकते हैं।

भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे से जो हासिल किया–

- अमेरिका भारत को भारत को 24 एमएच व 60 आर हेलिकॉप्टर देगा
- इंडियन आर्मी के लिए 6एच व 64ई अपाचे हेलिकॉप्टर की खरीदारी भारत करेगा।
- इंडियन नेवी के लिए मल्टी मिशन एयरक्रॉफ्ट भी भारत अमरीका से हासिल करेगा।

जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत की यात्रा की तैयारी कर रहे थे तभी अमरीका के चार प्रमुख सिनेटर्स, क्रिस वान हालेन, टोड यंग, रिचर्ड जे डर्बिन और लिंडसे

ओ ग्राह्म ने अमरीका के विदेश मंत्री माइक पंपियों को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया कि जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत जाएं तो वह कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा जरूर उठाएं। इन सिनेटरों ने अपने पत्र में लिखा कि 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटा दिया, तक से अब तक वहां के लोगों पर तमाम पाबंदियां लगी हुई हैं। पाकिस्तान लगातार अमरीका में इस मुद्दे पर लाबिंग कर रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप पर प्रभाव का परिणाम है या फिर राष्ट्रपति ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास कि दौरे पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि धारा 370 हटाने का मोदी सरकार का निर्णय उनका आंतरिक मामला है और प्रधानमंत्री कश्मीर पर काम कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर पर आवश्यक हुआ तो उन्हें मध्यस्थता करने में खुशी होगी, लेकिन साथ ही यह भी जोर देकर कहा कि भारत और पाकिस्तान मिल कर इसे सुलझा सकते हैं। इससे ज्यादा भारत के लिए क्या उपलब्धि हो सकती है कि यूरोप और अमरीका पाकिस्तान के इस प्रोपोगेंडा को गिरा दें कि कश्मीर में मानवाधिकार हनन हो रहा है और उस पर अंतराष्ट्रीय शक्तियां हस्तक्षेप करें।

एक वह भी समय था जब तत्कालिन प्रधानमंत्री नरसिह राव के

ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास है कि दौरे पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि धारा 370 हटाने का मोदी सरकार का निर्णय उनका आंतरिक मामला है और प्रधानमंत्री कश्मीर पर काम कर रहे हैं।

एक बार कहने पर तब के विपक्ष के नेता स्व अटल बिहारी वाजपेयी जेनेवा में होने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग की बैठक में भारत के अधिकारिक दल का नेतृत्व करने सहज चले गए और वहां उन्होंने कश्मीर के कथित मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा भारत पर प्रतिबध लगाए जाने के प्रस्ताव को गिराने में प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री मोदी के इस नाजुक घड़ी में सहयोग की बात आई, तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाकर काम किया। पहले तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए उलूल जुलूल बातें की, फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्रंप के स्वागत पर होने वाले खर्चें पर आपत्ति दर्ज की, और सबसे बड़ी बात कि सामान्य कूटनीतिक जरूरतों को पूरा करने में भी कांग्रेस ने सामान्य शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया। सोनिया गांधी को निमंत्रण ना मिलने का मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में दिए भोज का बायकाट कर दिया। यहां तक कि पूर्वप्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतिम समय में भोज में शामिल होने से मना कर दिया। कांग्रेस का यह व्यवहार देशहित के सरासर खिलाफ था। बावजूद इसके अपने आतिथ्य सत्कार से राष्ट्रपति ट्रंप गदगद नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उद्गार की सभी उपमाओं का उपयोग किया।

और अंत में षडयंत्र पूर्वक कुछ लोगों ने नागरिक कर्त्तव्यों के पालन के बजाय राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को एक बुरे अनुभव में बदलने के लिए जो कृत्य किया, वह एक देश के रूप शर्मसार करने के लिए काफी है। दिल्ली में दंगे के लिए कुछ बयानों और सोशल मीडिया पर चल रहे संदेशों को ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, वे षडयंत्रकारी भी जिम्मेदार हैं जो यह बयान देते नजर आए कि दिल्ली में दंगा सरकार नियोजित है। गृहमंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, दिल्ली जल रही है और मोदी अमरीकी राष्ट्रपति के साथ फोटो खिचवाने में लगे हैं। इन सभी लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे से गुरेज है, वे टुकड़े टुकड़े भारत के हामी हैं। जिन्होंनें आजादी शब्द को सरकार के खिलाफ मुहाबरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, जिन्हें देशहित से ज्यादा मोदी विरोध प्यारा है।

राष्ट्रपति ट्रंप का दौरा कूटनीति की किताबों में एक बेहद सफल दौरे के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन साथ में यह भी उद्धृत होगा कि इस कुटनीतिक सफलता का रस्सास्वादन लेने के बजाय gead Mtsv ubjlo d s?kw i j ks sx, A❑❑

https://www.indiaintheworld.in/

भारतीय आर्थिकी के अनुकूल नहीं है आभासी मुद्रा

सरकारी बैंकों पर लगातार बढ़ते एनपीए के दबाव तथा निजी क्षेत्र के एक बड़े बैंक (यस बैंक) के डूब के कगार पर पहुंचने की खबरों के बीच उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था में आभासी मुद्रा को हरी झंडी दिये जाने से आर्थिक जानकारों के कान खड़े हो गये है। कुछ कारोबारियों ने हालांकि इसे प्रचलन में बनाये रखने के लिए नियमन की मांग की है, पर आर्थिक विशेषज्ञों ने फिलहाल इसे जोखिम भरा कदम माना है। स्वदेशी जागरण मंच ने भी आभासी मुद्रा के प्रचलन पर सवाल उठाते हुए इससे आम उपभोक्ताओं पर आसन्न खतरे की आशंका व्यक्त की है।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने क्रिप्टो करेंसी यानि आभासी मुद्रा पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया। अब लोग बिना रोक–टोक इसमें लेनदेन कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने 2018 में इस पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध के खिलाफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया ने याचिका दाखिल की थी।

मालूम हो कि क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, जो मूर्तरूप में उपलब्ध नहीं होती, यह केवल आभासी मुद्रा है। इसका उपयोग लेनदेन के लिए किया जाता है। इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसमें कूट लेखन का प्रयोग होता है। इसके इस्तेमाल में धोखाधड़ी की आशंका बहुत कम होती है।

इंटरनेट पर वर्चुअल करेंसी की शुरुआत जनवरी 2009 में बिटकॉइन के नाम से हुई थी। वर्तमान में बाजार में इसके अलावा और भी कई मुद्राएं, मसलन एथेरियम, रिपल और कारनाडो आदि मौजूद है। फिलहाल 2116 क्रिप्टोकरेंसी प्रचलन में है। जिनकी बाजार में कुल पूंजी लगभग 119 अरब डालर है। कैंब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 2017 में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 58 लाख लोग उस समय आभासी मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे थे। अब तो भारत में ही बिटकॉइन के 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। सामान्य मुद्रा की तरह आभासी

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने चिंता प्रकट की है तथा कहा है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नये किस्म की उथल–पुथल की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि इसके खतरों से निपटने में भारत का कानूनी और मौद्रिक ढांचा अभी समर्थ नहीं है।

– स्वदेशी संवाद

मुद्रा का हालांकि बैंक से कोई लेना–देना नहीं है। बाजार के उतार–चढ़ाव से भी मुक्त है। इसका लेनदेन गैरकानूनी तरीके से होने के कारण इससे जुड़े विवाद में किसी को सजा नहीं दी जा सकती।

आभासी मुद्रा को फिलहाल लेनदेन का सरल तरीका माना जाता है। जर्मनी के वित्त मंत्रालय ने इसे खाते की एक इकाई के रूप में मान्यता दे दी है। लेकिन अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ने इससे संबंधित सिल्करोड नाम के ऑनलाइन फार्म को बंद कर दिया है। क्योंकि वहां इसके जरिए फर्जीवाड़ा का मामला प्रकाश में आ रहा था। आभासी मुद्रा के पूरी तरह से चलन में आ जाने के बाद निश्चित तौर पर देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा। लेकिन इसका स्वरूप कैसा होगा, यह बताना अभी मुश्किल है। माना जाता है कि आभासी मुद्रा के वैध मुद्रा बनने के बाद बैंकों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और आर्थिक क्षेत्र के बहुत सारे मानक भी बदल जाएंगे। सवाल है कि ऐसे लोग जो न सिर्फ आज बल्कि लंबे समय से आभासी मुद्रा से अनजान रहेंगे, वह अपने पैसे कहां रखेंगे? जरूरत पड़ने पर कर्ज किससे लेंगे? विवाद होने पर निपटारा कौन करेगा? इन प्रश्नों के जवाब आभासी मुद्रा के पैरोकारों के पास फिलहाल नहीं है।

कुछ महीने पहले बंगलुरु में देश का पहला बिटकॉइन एटीएम खोलने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इस एटीएम के जरिए कारोबारी अपने क्रिप्टो वायलेट में रुपए जमा कराकर आभासी मुद्रा में कारोबार करना चाहते थे। जरूरत पड़ने पर वे इस एटीएम से रुपयों की निकासी भी कर सकते थे। इसके लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। शुरू में इस एटीएम से जमा और निकासी की सीमा 1000 रूपये

आभासी मुद्रा के कारोबार में हो रही बढ़ोतरी यह बताती है कि इसमें कारोबार करने वाले इस पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। इस बीच आभासी मुद्रा के एक्सचेंजरों ने इस मुद्रा में परस्पर कारोबार की सुविधा देकर इस पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है।

रखी गई थी और भविष्य में निकासी की अधिकतम सीमा डेढ़ से दो लाख रूपये तक किए जाने की संभावना थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण यह एक्सचेंज क्रिप्टी कारोबार को बढ़ाने के नए विकल्पों की तलाश कर रहा था। इसके प्रयास से ही क्रिप्टो एटीएम के रूप में नया विकल्प सामने आया था। उम्मीद थी कि यह मुक्त रूप से कार्य कर सकेगा। आभासी मुद्रा के कारोबार में हो रही बढ़ोतरी यह बताती है कि इसमें कारोबार करने वाले इस पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। इस बीच आभासी मुद्रा के एक्सचेंजरों ने इस मुद्रा में परस्पर कारोबार की सुविधा देकर इस पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है।

कुछ कारोबारियों का भी मानना है कि इस कारोबार पर प्रतिबंध लगाने से अच्छा है कि इसका नियमन किया जाए और इस संबंध में स्पष्ट कानून बनाया जाए। क्योंकि भारत में आभासी मुद्रा के भविष्य का निर्धारण होना अभी बाकी है। रिजर्व बैंक का कहना है कि आभासी मुद्रा की अपनी कोई कीमत नहीं होती और इसके द्वारा अवैध कारोबार किए जाने की आशंका बहुत ज्यादा है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि इनकी कीमतों में उतार–चढ़ाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है। रिजर्व बैंक के अनुसार आभासी मुद्रा को सहेजने के लिए बनाए गए वायलेट के साथ पासवर्ड चोरी, हैकिंग जैसी समस्याएं मौजूद हैं। इन खतरों को लेकर रिजर्व बैंक लंबे समय से लोगों को आगाह करता रहा है।

फरवरी 2017 में रिजर्व बैंक ने आभासी मुद्रा के कारोबारियों और इससे जुड़े लोगों को ग्राहक हितों और सुरक्षा संबंधी विधिक और कानूनी खतरों से सावधान किया था। इस मुद्रा को किसी टकसाल में नहीं ढ़ाला जाता है, इसलिए इसका लेनदेन दूसरी मुद्राओं की तरह वैधानिक नहीं है। बिटकॉइन का लेनदेन सार्वजनिक होता है, पर उपयोगकर्ता की पहचान गुप्त होने के कारण कोई गड़बड़ी होने पर दोषी का पकड़ में आना मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आभासी मुद्रा पर प्रतिबंध हटाने से इसका उपयोग करने वाले कारोबारियों को अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन इससे जुड़े जोखिम अपनी जगह पर बने रहेंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा आभासी मुद्रा पर लगे बैन को हटाये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने चिंता प्रकट की है तथा कहा है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नये किस्म की उथल–पुथल की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि इसके खतरों से निपटने में भारत का कानूनी और मौद्रिक ढांचा अभी समर्थ नहीं है। इसलिए सरकार को इससे संबंधित दिशा–निर्देश जारी करने चाहिए और जहां तक संभव हो वहां तक इसे नियमों के दायरे में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक देश में इस बावत उचित कानूनी प्लेटफार्म तैयार नहीं कर लिया जाता, ऐसे किसी भी प्रयोग से बचना हितकर होगा। ❑❑

कठघरे में फसल बीमा योजना

किसान जस के तसः बीमा कंपनियों की चांदी

बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। देश के कई हिस्सों के किसान नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुश्किल में सहायता के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को इस बावत लगाया है लेकिन बीमा कंपनियों के रवैये के कारण किसानों में उदासीनता का आलम है।

किसानों को नहीं लगता कि सरकार द्वारा घोषित मुआवजा बीमा कंपनियां उन्हें मौके पर दे पायेंगी। बीमा कंपनियों का ट्रैक रिकार्ड भी इसकी पुष्टि करता है। वहीं बीमा कंपनियों का रोना है कि किसान बीमा योजना में जिस संख्या में पंजीकृत होने चाहिए था, वे नहीं हुए, ऐसे में उनके हाथ सीमित है। लेकिन लाख टके का सवाल है कि जब किसानों को बीमा वाली फसल का समय पर मुआवजा नहीं मिलेगा और सरकारी तंत्र द्वारा तबाह फसल का सटीक आकलन भी नहीं होगा, तो भला किसान अनावश्यक रूप से फसल बीमा योजना का बोझ क्यों उठाएंगे?

सरकार के ही आंकड़ों पर अगर गौर करें तो वर्ष 2016–17 में चार करोड़ चालीस लाख किसानों ने तकरीबन 382 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था। फसलों के नुकसान का आंकलन कर बीमा कंपनियों ने किसान को सिर्फ 10525 करोड रुपए मुआवजे के तौर पर दिए। जबकि केंद्र और राज्य सरकारों ने इन बीमा कंपनियों को 131018 करोड रुपए प्रीमियम के तौर पर दिया। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि फायदे से किसकी झोली भरी।

अब जरा 2017–18 के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक वर्ष में ही फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या चार करोड़ चालीस से घटकर तीन करोड़ उन्नचास लाख रह गई और कृषि क्षेत्रफल 382 लाख घटकर 343 लाख हेक्टेयर रह गया। 2017–18 में केंद्र व राज्य सरकारों ने बीमा कंपनियों को प्रीमियम के तौर पर 129295 करोड रुपए दिए। जबकि किसानों को मुआवजे के तौर पर सिर्फ 17707 करोड रुपए मिले। इस बार भी मुनाफे में बीमा कंपनियां ही रही।

लाख टके का सवाल है कि जब किसानों को बीमा वाली फसल का समय पर मुआवजा नहीं मिलेगा और सरकारी तंत्र द्वारा तबाह फसल का सटीक आकलन भी नहीं होगा, तो भला किसान अनावश्यक रूप से फसल बीमा योजना का बोझ क्यों उठाएंगे?

– अनिल तिवारी

हैरान करने वाला तथ्य यह है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई फसल बीमा योजना के चार वर्ष पूरे होने को है। लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी तक 2017–18 के प्रीमियम का हिस्सा नहीं दिया गया। दूसरी ओर बिहार और पंजाब जैसे राज्यों ने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू ही नहीं किया। बहरहाल इन आंकड़ों से एक बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वास्तविक लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है और अब किसान किस्त के अनावश्यक बोझ से बचना चाहते हैं। वैसे भी गौर करें तो देश में 80 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं मध्यम श्रेणी के हैं। इनमें सिर्फ 40 प्रतिशत किसान व्यवसायिक खेती करते हैं। अधिकांश किसान अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करते हैं। ऐसे में बीमा का प्रीमियम देना उनके लिए कठिन है।

योजना के जरिए संदेश दिया गया कि प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद ही 25 फीसद सीधे किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। किसान की फसल ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान से नष्ट होती है तब भी उन्हें मुआवजा मिलेगा। इसको साधने के लिए फसल बीमा को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इस योजना में बटाई पर खेती करने वालों का भी ध्यान रखा गया। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों से ज्यादा बीमा कंपनियों को मिला। यह माना जा रहा था कि इस योजना को मूर्तरूप लेने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा और उड़ीसा के उन किसानों को अच्छा खासा भला होगा, जो बरसों से न सिर्फ सूखे की मार झेल रहे हैं, बल्कि कर्ज के बोझ से भी दबे हुए हैं। लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। आज भी देश का हर दूसरा किसान कर्ज में डूबा है। देश के 90 प्रतिशत किसान परिवारों से 52 प्रतिशत कर्ज के बोझ तले हैं और हर किसान पर औसतन 45000 रूपये से अधिक का कर्ज है।

भारत में कृषक परिवारों की स्थिति के मुख्य शीर्षक वाली रिपोर्ट की मानें तो आंध्र प्रदेश के 52 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबे हैं। उत्तर प्रदेश में 44 प्रतिशत, झारखंड में 42, हरियाणा में 42 और पश्चिम बंगाल में 39 प्रतिशत है। कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक कर्ज के जाल में फंसे किसानों ने न सिर्फ बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हुए हैं, बल्कि आत्महत्या भी कर रहे हैं। सरकार की नीतियों का नतीजा है कि देश में किसानों की संख्या लगातार घट रही है। एक आंकड़े के मुताबिक 2001 में देश में 13 करोड़ किसान थे, जो 2011 में घटकर केवल 11 करोड़ 86 लाख रह गये। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले वर्ष में 31 लाख किसानों ने खेती छोड़ी है। खेती की जमीन का कम होना, खेती में लागत का अधिक होना, रियल स्टेट के लिए अधिग्रहण आदि इसके लिए बड़े कारण हैं। इसके अलावा प्रकृति पर आधारित कृषि देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ एवं सूखे का प्रकोप, प्राकृतिक आपदा से और कर्ज के कारण बड़े पैमाने पर किसान खेती छोड़ रहे हैं। पिछले एक दशक के दौरान महाराष्ट्र में सर्वाधिक 756000, राजस्थान में 478000, आसाम में 330000 किसानों ने खेती का काम छोड़ दिया। इसी तरह उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल जैसे छोटे राज्यों में भी किसानों की संख्या घटी है। गौरतलब है कि 1000 हेक्टेयर खेती की जमीन कम होने पर 100 किसानों और 760 खेतिहर मजदूरों की आजीविका छीनती है। आज देश में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.18 हेक्टेयर रह गई है। 82 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं और उनके पास कृषि भूमि 2 हेक्टेयर है या उससे भी कम रह गई है। कृषि क्षेत्र की विकास दर भी घट रही है। वर्ष 1950–51 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी लगभग 52 प्रतिशत थी जो घटकर 27 प्रतिशत के आसपास रह गई है। यह सही है कि उद्योग धंधे कल–कारखाने एवं सेवा क्षेत्र में सतत विकास की वजह से कृषि की भागीदारी कम हुई है। लेकिन पिछले तीन दशक में कृषि पर निर्भर आबादी में इजाफा दर्शाता है कि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का अनुपातिक फैलाव नहीं हुआ है। दूसरी और खेती के विकास में क्षेत्रवार विषमता का बढ़ना प्राकृतिक बाधाओं को पार कर पाने में विफलता, भूजल का खतरनाक स्तर तक पहुंचना और हरित क्रांति वाले इलाकों में पैदावार की कमी आना और भी चिंताजनक है। हैरानी की बात यह है कि इस दिशा में सुधार के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस पहल आज तक नहीं हुई। जिन क्षेत्रों में सरकारें खेती की जमीन को अधिग्रहित कर रही है। उनमें विस्थापन की भी विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अपनी जमीन गंवाने के बाद किसानों के पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया है। लिहाजा वे खानाबदोश की तरह जीवन गुजारने को विवश हैं। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों और कृषि की सूरत बदलेगी, लेकिन उसका सारा फायदा तो बीमा कंपनियां ले उड़ी। केंद्र सरकार द्वारा 2016 में प्रारंभ की गई फसल बीमा योजना से किसानों का मोहभंग शुरू हो गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि गत 4 वर्षों के दौरान इस योजना के तहत किसानों की संख्या और कृषि योग्य उनके क्षेत्र में कमी आई है। दूसरी तरफ सरकारी और निजी बीमा कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है। ❑❑

कोरोना वायरस एक वैश्विक चुनौती

बचपन में मेरे गांव में रघुवीर बाबा को टीबी की बीमारी हुई थी। उन्हें गांव के बाहर बगीचे में रखा गया था। घर के लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर उन्हें खाना, पानी, दवा देने जाते थे। एक तरह से यह मान लिया गया था कि अब वे नहीं बचेंगे। लेकिन उन्हीं दिनों विज्ञान के दम पर विकसित दवाईयों ने उन पर असर किया और वे दो–तीन महीने बाद खुद उठकर घर आये। आगे बढ़ते समय और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हो रही प्रगति से यह उम्मीद की जाने लगी कि दवाइयों के भरोसे सारे रोगों को टाला जा सकता है। कई मामलों में ऐसा हुआ भी है। बीमारियों का समय रहते पता लगाकर दवाओं और शल्यक्रिया के बल पर बुखार से लेकर कैंसर और दिल की किडनी से लेकर अनेक असाध्य समझी जाने वाली समस्याओं को इंसान ने अपने काबू में कर लिया है। लेकिन अब, अचानक दुनिया भर में फैले 'करोना' जैसे वायरस ने एक बार फिर समय का पहिया घुमाते हुए यह साबित कर दिया है कि इलाज के चाहे जितने अच्छे इंतजाम कर लिए गए हों, पृथ्वी पर मानव सभ्यता के लिए चुनौतियां शायद कभी खत्म नहीं होंगी।

ऐसी ही एक चुनौती आज दुनिया के सामने कोरोना वायरस के रूप में आ धमकी है। दुनिया के पास इससे लड़ने की कोई कारगर दवा नहीं है। खासकर वैसा कोई टीका उपलब्ध नहीं है, जिस तरह से हैजा, फ्लू, चेचक और पोलियो तक के लिए टीके उपलब्ध है। आज अगर ऐसा कोई टीका हमारे पास होता तो यह बात बेहिचक कही जा सकती थी कि कोरोना संकट की चुनौतियों को चुटकी बजाकर हल कर लिया जाएगा। और दुनिया आज जिस तरह से आतंकित है उसकी नौबत शायद नहीं आती।

कोरोना चीन के बुहान शहर से बीते साल दिसंबर में फैलना शुरू हुआ। इसे मेडिकल भाषा में कोविन–19 का नाम दिया गया है। अब तक इसने दुनिया के 120 से ज्यादा देशों को चपेट में ले लिया है। चीन में इसका असर सबसे अधिक है, जहां 5000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और दुनिया में करीब एक लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं। भारत में भी अब तक इसके 50 से अधिक मामले की तस्दीक हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य

वैज्ञानिक अब इस बात की खोज करने में लगे हैं कि आखिर यह करोना वायरस लोगों में फैल कैसे रहा है? बुजुर्गों में मौत के आंकड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है कि चूंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए बच्चों की अपेक्षा बुजुर्गों को यह जल्दी मौत की ओर ढकेल रहा है।

– वैदेही

संगठन भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुका है। इस आपातकाल के तहत भारत सहित कई देशों में हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों में संक्रमण की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। अब तो भारत में 13 अप्रैल तक वीजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन के हर तरह के दौरों को रोक दिया गया है। ऐसे उपायों को देखें तो यह कह सकते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना की रोकथाम के लिए चाक–चौबंद हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कोरोना का इलाज क्या है? इस बारे में सच्चाई है कि फिलहाल दुनिया के स्वास्थ्य तंत्र के पास कोरोना से निपटने की कोई सटीक दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कोरोना के मरीजों का इलाज उनमें दिखने वाले लक्षणों के आधार पर किया जा रहा है। संक्रमित लोगों को अस्पतालों में अलग कमरों में रखा जा रहा है और बुखार व दर्द की दवाई देकर यह लक्षण कम करते हुए उम्मीद की जा रही है कि वक्त के साथ तापमान बढ़ने पर कोरोना का असर कम हो जाएगा और मरीज स्वस्थ हो जाएंगे। उम्मीद है कि यह उपाय कारगर होंगे और कोरोना का खौफ भी कम हो सकेगा।

यह मानने से इंकार नहीं कि जिस प्रकार दुनिया में साधारण सर्दी जुखाम के खिलाफ वैक्सीन मौजूद है, उसी तरह यदि कोरोना वायरस के हमले की धार कम करने वाले टीके उपलब्ध होते तो आज हालात इतने विकट नहीं होते। टीका लगाने के पीछे मूल मकसद यही है कि किसी व्यक्ति या जीव में वांछित बीमारी के बिना ही उसके शरीर में ऐसे जीवाणु विकसित कर दिए जाएं जो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इस तरह विकसित कर दें, ताकि शरीर में उस बीमारी के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा हो जाए। चेचक की बीमारी के

जेनेटिक कोड बताता है कि इस बीमारी का उद्भव क्या है? किन हालात में यह संक्रमण बढ़ सकता है और जीवित रह सकता है? और इसका खात्मा कैसे मुमकिन है?

खात्मे के पीछे ऐसे ही टीकाकरण की अहम भूमिका रही थी। अब तो कई ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जिनमें इंजेक्शन या मुंह से दी जाने वाली दवा यानी टीका का प्रचलन बेहद आम हो गया है। इन तीनों की उपयोगिता यह है कि इनके लगाने के बाद कोई व्यक्ति या तो जीवन भर या फिर एक निश्चित समय सीमा तक संबंधित बीमारी के असर से मुक्त हो जाता है। एक दौर था जब दुनिया टीकों के बारे में नहीं जानती थी। चेचक, पोलियो जैसी बीमारियों ने दुनिया में कहर बरपा रखा था। लेकिन जब फ्रांस के जीव विज्ञानी लुई पाश्चर ने इस विषय का टीका तैयार किया तो दुनिया को बीमारियों की रोकथाम का एक रास्ता मिल गया। लुई पाश्चर के बाद एक उल्लेखनीय काम एडवर्ड जेनर ने किया जिन्होंने चेचक के टीके का विकास किया। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके पर एक शोध पत्र लिखा था जिससे टीका का दुनिया में प्रचार हुआ। जहां तक पोलियो के टीके का सवाल है तो यह पिछली सदी के छठे दशक में सामने आया था। अमेरिका के पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जोनास साल्क ने 1952 में पोलियो टीके के विकास का दावा किया था। इस घोषणा के साल भर बाद 1953 को उन्होंने अमेरिकी रोडियो पर ऐलान किया कि 1 साल की अवधि में उन्होंने पोलियो के टीके का बच्चों पर परीक्षण किया है और कारगर पाया है। मालूम हो कि किसी भी संक्रमण का टीका बनाने की शुरुआत उस वायरस के जेनेटिक कोड का पता लगाने से होती है। जेनेटिक कोड बताता है कि इस बीमारी का उद्भव क्या है? किन हालात में यह संक्रमण बढ़ सकता है और जीवित रह सकता है? और इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? इस बारे संतोष की बात यह है कि इस साल 10 जनवरी को चीन ने कोरोनावायरस का जेनेटिक कोड दुनिया के साथ साझा कर दिया है। यह रिपोर्ट साझा करने का अभिप्राय यह है कि इसके तहत वायरस का अनुवांशिक क्रम बताया गया है। जिससे वायरस में आने वाले बदलावों और इसके उस व्यवहार व तरीकों का अंदाजा लगता है। इसे एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में फैलने की ताकत देता है। इससे यह जानकारी भी मिलती है कि यह वायरस तेजी से फैलता है या धीमी गति से। चीन के नेशनल क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च सेंटर और सदर्न यूनिवर्सिटी सैमसंग टेक्नोलॉजी की संयुक्त टीम ने इसका पता लगाया है। इससे वायरस की पहचान, उसके विश्लेषण और जरूरी शोध के लिए महत्वपूर्ण रास्ता साफ हो सकता है। वायरस की एक तस्वीर मिली है जिसे हॉस्पिटल ने जारी की है। शोध करने वाली टीम के सदस्य प्रोफेसर चाउइन ने कहा है कि वायरस की उपस्थिति से हम देखेंगे कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रकृति में होता है। वैज्ञानिक अब इस बात की खोज करने में लगे हैं कि आखिर यह कोरोना वायरस लोगों में फैल कैसे रहा है? बुजुर्गों में मौत के आंकड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है कि चूंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए बच्चों की अपेक्षा बुजुर्गों को यह जल्दी मौत की ओर ढकेल रहा है। ❑❑

अभी भी चौराहे पर है अफगानिस्तान का भविष्य

अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौते पर 29 फरवरी 2020 को हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर अमेरिकी वार्ताकार जलमय खलीलजाद तथा तालिबान के उपनेता मुल्ला बिरादर ने हस्ताक्षर किए। इस समय अमेरिका और तालिबान के प्रतिनिधियों के अलावा लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि भी वहां पर उपस्थित थे। भारत के प्रतिनिधि के रूपमें कतर में भारतीय राजनयिक पी. कुमारन भी समारोह में मौजूद थे। अमेरिकी वार्ताकार जलमय खलीलजाद ने तालिबान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। जलमय खलीलजाद अफगानी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं तथा इससे पहले अफगानिस्तान तथा इराक में अमेरिकी राजदूत भी रह चुके हैं। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच इससे पहले कई दौर की वार्ताएं हो चुकी थी। 10 मार्च को अमेरिका और तालिबान के बीच नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दोबारा बैठक होने की संभावना है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है।

सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पठान, उजबेक, पश्तून, हजारा और ताजिक मिलकर अफगानिस्तान को एक देश के रूप में एकता स्थापित कर पाएंगे या फिर सत्ता की सियासी जंग शुरू हो जाएगी।
– **दुलीचन्द कालीरमन**

रणनीतिक तौर पर यह तालिबान की जीत है। क्योंकि इस समझौते से अमेरिका के साथ मुख्य वार्ताकार तालिबानी थे। जिन्हें अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो गई है। अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को मुख्य भूमिका में नहीं रखा गया है। अमेरिका समझौते के मुताबिक अगले 2 से 3 महीने में अपनी सेनाओं की संख्या को मौजूदा 14000 से घटाकर 8600 कर देगा तथा अगले 14 महीने में अपनी समस्त सेनाओं को अफगानिस्तान से निकाल लेगा। इस समझौते को अगले 135 दिनों में लागू किया जाएगा। अफगानिस्तान में स्थित तालिबानी नेतृत्व ने अमेरिका को इस बात का विश्वास दिलाया है कि उसकी भूमि से आईएसआईएस तथा अलकायदा जैसे कट्टर इस्लामी आतंकवादी संगठनों द्वारा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि अमेरिका के सहयोगियों में भारत का भी नाम है या नहीं।

आशंका जताई जा रही है कि मध्य पूर्व के देशों में इस्लामिक स्टेट और अल कायदा की हार के बाद उनके लड़ाकों के लिए अफगानिस्तान एक सुरक्षित पनाहगाह बन सकता है। जिससे वहां शांति की सभी संभावनाएं कुचली जा सकती है। इसके साथ–साथ इस क्षेत्र में फैली वहाबी–विचारधारा की कट्टरता भी इसमें सबसे बड़ा खतरा है। जिसको समय–समय पर पाकिस्तान से वैचारिक खाद–पानी मिलता रहता है। अफगानिस्तान की

लगभग सारी युवा आबादी ने जब से होश संभाला है, तब से अपने देश में हिंसा और तबाही ही देखी है।

अमरीका और तालिबान के बीच समझौते में विश्वास बहाली के लिए इस समझौते के 10 मार्च 2020 से शुरू होने से पहले अफगानिस्तान की सरकार द्वारा 5000 तालिबानी लड़ाकों को रिहा किया जाना था। इसके बदले में तालिबान द्वारा लगभग 1000 अफगानी सैनिकों को रिहा किया जाना था। लेकिन समझौते के वास्तविक रूप में अमल से पहले ही एक मार्च 2020 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा तालिबान लड़ाकों को छोड़ने से मना कर दिया गया।

डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी घोषणा पत्र के कारण अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान के चंगुल से निकालना चाह रहा है। इराक की तरह अफगानिस्तान में तैनात ज्यादातर अमेरिकी सैनिक अमेरिका के दक्षिणी छोर के निवासी हैं। जिनकी राजनीतिक ताकत ज्यादा है और यह क्षेत्र रिपब्लिक पार्टी का गढ़ माना जाता है। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों और देशों में अपने सैनिकों को भेजते रहे हैं। जबकि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिकों की वैश्विक तैनाती को अमेरिका के नागरिकों पर अनावश्यक कर का बोझ मानते हैं। अमेरिका वर्ष 2001 से अफगानिस्तान में युद्ध पर 778 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है, जिसमें 44 बिलीयन डॉलर पुनर्निर्माण के कार्य में खर्च किए गए हैं। अभी भी अफगानिस्तान में 14000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।

19 वर्ष लंबे इस युद्ध में अमेरिका के 2300 सैनिकों की शहादत हुई है तथा 20660 सैनिक घायल हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2009 के बाद से ही लगभग एक लाख अफगानी नागरिक भी इस लंबे युद्ध में मारे जा चुके हैं।

तालिबान के हक्कानी गुट के उपनेता रियाजुद्दीन हक्कानी के अनुसार अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद अफगानिस्तान में राजनीतिक व्यवस्था कायम करने की दिशा में ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसमे हर अफगानी की हिस्सेदारी हो। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग लिया जाएगा तथा अमेरिका की भी भूमिका हो सकती है। लेकिन तालिबान के इस हृदय परिवर्तन पर कोई भी देश विश्वास नहीं कर पा रहा है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति असरफ गनी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह और राष्ट्रपति असरफ गनीके बीच राजनीतिक मतभेद भी जगजाहिर हैं। अफगानिस्तान के चुनाव आयोग को नकार चुके अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह और जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम मिलकर एक समानांतर सरकार के गठन का ऐलान कर चुके हैं।

गौरतलब है कि जब से यह शांति समझौता हुआ है। उसके बाद भी तालिबान द्वारा अफगानी सेना पर हमला किया जा चुका है। जिसके जवाब में अमेरिकी सेनाओं द्वारा तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। तालिबान द्वारा काबुल में एक राजनीतिक रैली में हमला करके 27 शियाओं की हत्या कर दी गई। ऐसे वातावरण में इस शांति समझौते पर प्रश्नचिन्ह लगनेशुरू हो चुके। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पठान, उजबेक, पश्तून, हजारा और ताजिक मिलकर अफगानिस्तान को एक देश के रूप में एकता स्थापित कर पाएंगे या फिर सत्ता की सियासी जंग शुरू हो जाएगी। जिससे अफगानिस्तान का पुराना रिश्ता और इतिहास भी रहा है। अफगानिस्तान अगर अबकी बार इस मौके को गंवा देता है तो वह निरंतर बदलती दुनिया में बहुत पीछे छूट जाएगा।

अमरीका अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका चाहता है। एक अनुमान के अनुसार भारत से सैन्य टुकड़ी अफगानिस्तान भेजी जा सकती है। जिसे अफगान सैन्य बलों को प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का परिचायक होगा। लेकिन अति आत्मविश्वास के भी अपने खतरे हैं।

शांति सेना के रूप में भारतीय सेना का प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर स्थिति किन्ही कारणों से संघर्ष तक पहुंची तो स्थानीय जनता विदेशी सेना के खिलाफ हो जाती है, जिसके अपने खतरे हैं। भारत को ऐसी स्थिति से बचना होगा। क्योंकि हम अपने हाथ लंका में एलटीटीई के विरुद्ध पहले ही जला चुके हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपनी संसद में कहा कि भारतीय सेनाओं को अफगानिस्तान में किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत की अफगानिस्तान में कोई भूमिका हो।

भारत अभी तक युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर चुका है। जिसमें अफगानिस्तान की संसद, सड़कें,नदियों पर पुलों का निर्माण तथा अस्पतालों का निर्माण शामिल है। अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए अमेरिका और तालिबान में हुए समझौते को लेकर भारत ने खुशी जाहिर की है विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में अफगानिस्तान में शांति सुरक्षा और स्थायित्व लाने के प्रयासों का समर्थन किया है भारत ने कहा है कि पड़ोसी होने के नाते हम आगे भी सरकार और अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करते रहेंगे। ❑❑

जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल

लाभ कमा रही है सार्वजनिक इकाइयां

सरकार ने भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कोनकोरनाम की तीन सार्वजनिक इकाई का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। निजीकरण के अंतर्गत इन इकाइयों के सरकार के पास जो शेयर हैं उन्हें किसी विशेष निजी खरीदार को एकमुश्त बेच दिया जायेगा। इस बिक्री के बाद खरीदार के हाथ में इन इकाइयों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जायेगा। इस कदम का स्वागत करना चाहिए क्योंकि सरकारी इकाइयों द्वारा जनहित नहीं, बल्कि जनता की हानि की जाती है। ये अकुशल है। अतः इन्हें सरकारी दायरे में रखने से इनके द्वारा अर्जित घाटे की भरपायी जनता की गाढ़ी कमायी से की जाती है। इनके निजीकरण से जनता को राहत मिलेगी।

साथ–साथ सरकार ने दो जल विद्युत कंपनियों को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) को बेचने का निर्णय लिया है। इन दोनों सरकारी कंपनियों को तीसरी सरकारी विद्युत कंपनी को बेचा जायेगा। ये दो कंपनियां है– नार्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (नीपको), जोकि पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत बनाती है और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी), जो उत्तराखंड में जल विद्युत बनाती है। इन दोनों इकाइयों के सरकारी शेयरों को तीसरी सरकारी इकाई एनटीपीसी को बेच दिया जायेगा। इन ईकाईयों पर सरकार का नियंत्रण पूर्ववत बरकरार रहेगा। वर्तमान में इन इकाइयों पर सरकार नियंत्रण सीधा है। उर्जा मंत्रालय के सचिव इनका नियंत्रण करते हैं। प्रस्तावित विनिवेश के बाद भी उर्जा मंत्रालय के सचिव ही इन कंपनियों पर नियंत्रण करेंगे। अंतर सिर्फ यह होगा कि उर्जा मंत्रालय के सचिव द्वारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) पर नियंत्रण किया जायेगा और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अधिकारी इन इकाइयों का नियंत्रण करेंगे। केवल टोपी बदल जाएगी।

यह घुमावदार नियंत्रण अनुचित है क्योंकि इन इकाइयों द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा है। टीएचडीसी द्वारा उत्पादित बिजली को विभिन्न राज्यों को 11 रुपए प्रति यूनिट में बेचा जा रहा है। यह बिजली आज इंडिया एनर्जी एक्सचेंज (IEX) में 3 रुपए में उपलब्ध

सरकार को चाहिए कि समस्त सार्वजनिक ईकाईयों की सामाजिक आकलन अथवा सोशल ऑडिट कराए कि इनके द्वारा जनहित वास्तव में हासिल हो रहा है या नहीं। इन्हें सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर इनका पूर्ण निजीकरण कर दे जिससे कि बाजार के आधार पर इनके कार्यकलाप का संचालन हो और इनके द्वारा महँगी बिजली बेचकर जनता का दोहन बंद हो।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में बिजली की खरीद बिक्री निरंतर चलती रहती है। अतः किसी भी राज्य के पास विकल्प है कि वह टीएचडीसीसे 11 रुपए में बिजली खरीदे अथवा 3 रुपए में इंडिया एनर्जी एक्सचेंज से। लेकिन तमाम राज्यों ने टीएचडीसी से खरीद के अनुबंध कर रखें हैं इसलिए ये महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हैं। इस महंगी बिजली को बेचकर टीएचडीसी भारी लाभ कमा रही है। 11 रुपए में बेची गई इस बिजली का बोझ अंततः देश के नागरिक पर पड़ता है जिसके द्वारा इस बिजली को खरीदा जाता है। इस प्रकार टीएचडीसी द्वारा जनता का दोहन किया जा रहा है।

और गंभीर बात यह है कि इस अनुचित लाभ का निवेश टीएचडीसी द्वारा एक और जल विद्युत परियोजना को बनाने में लगाया जा रहा है जो पुनः महंगी बिजली बनाकर हानि करेगी। जैसे दुकानदार घटिया माल बेचकर पहले उपभोक्ता को बेवकूफ बनाए और उसके बाद इस घटिया माल की बिक्री से हुए लाभ से पुनः और अधिक घटिया माल खरीदे उसी प्रकार की टीएचडीसी की हालत है।

टीएचडीसीद्वारा विष्णुगाड–पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, इस परियोजना को 2008 में केंद्र सरकार द्वारा 2400 करोड़ रुपये में बनाने की स्वीकृति दी गई थी। उस समय इस परियोजना से उत्पादित बिजली का दाम 2.26 रुपए प्रति यूनिट था। इस परियोजना को 2013 में बनकर तैयार होना था। लेकिन टीएचडीसी की अकुशलता के कारण यह परियोजना आज 2020 में भी बनकर तैयार नही हुई है। टीएचडीसी का कहना है कि यह 2022 में बनकर तैयार हो जाएगी। 2013 से 2023 की अवधि में इस परियोजना की लागत 2400 करोड़ से बढ़कर 4400 करोड़ रुपये हो गई है। तदनुसार इस परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली की लागत 2.26 रुपए से बढ़कर 5.06 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। जिस प्रकार अभी तक इस परियोजना को बनाने में देरी हुई है यदि टीएचडीसी का यही रवाया जारी रहा तो यह परियोजना 2022 में भी बनकर तैयार नहीं होगी और इस परियोजना से उत्पादित बिजली का मूल्य 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए भी हो सकता है।

विष्णुगाड–पीपलकोटी परियोजना द्वारा बनाई गई बिजली से जनता को नुकसान होगा क्योंकि वही बिजली इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पर वर्तमान में 3.07 रुपए प्रति यूनिट में उपलब्ध है। वर्ष 2011–14 में इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में बिजली का औसत मूल्य 3.38 रुपए प्रति यूनिट था। वर्ष 2015–19 में यह मूल्य घटकर 3.07 रुपए प्रति यूनिट हो गया है। यदि बिजली के मूल्य में गिरावट का यह कदम जारी रहा तो 2022 में यह घटकर 2.76 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। अर्थ हुआ कि विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली जो 5.06 रुपए में बेची जाएगी वह वास्तव में बाजार में 2.76 रुपए में उपलब्ध है। इस बिजली को महंगा बेचकर टीएचडीसी लाभ कमायेगी। यद्यपि यह जनता के लिए हानिप्रद है क्योंकि उसे अनायास ही महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। प्रश्न उठता है कि राज्य के बिजली बोर्डों द्वारा यह महंगी बिजली क्यों खरीदी जाये?

टीएचडीसी नें कई राज्य के बिजली बोर्डों के साथ अनुबंध कर रखे हैं जिसके अंतर्गत परियोजना से उत्पादित बिजली का मूल्य परियोजना की लागत के आधार पर तय होता है। जैसे यदि परियोजना पूर्व निर्धारित 2400 करोड़ रुपये में पूरी हो जाती तो बिजली का मूल्य 2.26 रुपए प्रति यूनिट होता। लेकिन परियोजना की लागत बढ़कर 4400 करोड़ हो गयी है इसलिए बिजली का मूल्य भी 5.06 रुपए प्रति यूनिट हो गया है। लेकिन क्योंकि राज्यों नें इस बिजली को खरीदने का अनुबंध कर रखा है और परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का मूल्य सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा तय होता है इसलिए राज्यों को इस महंगी बिजली को खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा।

लगभग ये ही हालत दूसरी ईकाई नीपको की है। इस परियोजना द्वारा भी कथित रूप से लाभ कमाया जा रहा है लेकिन महंगी बिजली बेची जा रही है। इस परियोजना की आतंरिक हालत का अंदाज इस बात से पता लगता है कि नीपको द्वारा 300 करोड़ रुपये के बांड बाजार में बेचने के प्रयास किया था लेकिन केवल 13 करोड़ रुपये के ही बिके। यानी बाजार को इस कंपनी पर भरोसा नहीं है।

टीएचडीसी और नीपको के शेयरों की बिक्री अपनी ही दूसरी इकाई को करने का उद्देश्य सिर्फ यह दिखता है कि सरकार अपने निवेश की उगाई कर सके। एनटीपीसी ने कुछ लाभ कमा रखे हैं। उस रकम का उपयोग वह टीएचडीसी और नीपको को खरीदने में लगाएगा और वह रकम केंद्र सरकार के हाथ में आ जायेगी। सरकार के दोनों हाथ में लड्डू हैं। शेयर के मूल्य मिल जायेगा और नियंत्रण बू सचिव महोदय के हाथ में ही रहेगा। इस प्रकार टोपी घुमाने से इन कंपनियों द्वारा जनता को महंगी बिजली बेचने का क्रम जारी रहेगा। सरकार को चाहिए कि समस्त सार्वजनिक ईकाईयों की सामाजिक आकलन अथवा सोशल ऑडिट कराए कि इनके द्वारा जनहित वास्तव में हासिल हो रहा है या नहीं। इन्हें सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर इनका पूर्ण निजीकरण कर दे जिससे कि बाजार के आधार पर इनके कार्यकलाप का संचालन हो और इनके द्वारा महँगी बिजली बेचकर जनता का दोहन बंद हो। ❑❑

यस बैंक संकटः

सबक सीखने की दरकार

लंबे समय से सरकारी बैंक एनपीए के संकट से गुजर रहे हैं। हालांकि देश के बैंकिंग जमाओं का 63 प्रतिशत हिस्सा सरकारी बैंकों के पास है, तो भी लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि उनका इन बैंकों में पड़ा पैसा डूब सकता है। उसका कारण है, लोगों का यह विश्वास कि सरकारी होने के कारण उन बैंकों में उनका पैसा पूर्णतया सुरक्षित है। देर सबेर सरकार द्वारा सहायता पैकेजों और विविध उपायों के बाद स्थिति बदलनी शुरू हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि जल्द ही सरकारी बैंक एनपीए संकट से बाहर हो जायेगें।

आज जब सरकारी बैंकों का एनपीए संकट समाप्त होने के कगार पर है, देश का एक महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र का बैंक (यस बैंक) जो देश का सातवां सबसे बड़ा बैंक है, भारी संकट में आ गया है। यूं तो इस बैंक के बारे में लंबे समय से अटकलें लग रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह संकट काफी बढ़ गया है। हालांकि इससे पहले भी कई निजी बैंकों के संकट के चलते लोगों में चिंता व्याप्त होती रही है, लेकिन किसी न किसी तरह से उनके संकट का हल भी निकलता रहा है। उदारीकरण की पिछले लगभग तीन दशकों में कई निजी बैंक अस्तित्व में आये और उनमें खासा विस्तार भी देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक पहला और आईसीआईसीआई बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनने में कामयाब हो गया, एक्सिस बैंक एवं कोटक बैंक सहित कई निजी क्षेत्र के बैंक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर पाये।

यस बैंक के वर्तमान संकट से उबरने के लिए फिलहाल रिजर्व बैंक ने इसके जमाकर्ताओं पर एक अंकुश लगा दिया है कि वे एक महीने में पचास हजार और विशेष परिस्थितियों जैसे बीमारी, विवाह इत्यादि के लिए 5 लाख रूपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर पायेंगे। यस बैंक को गहरे संकट से बचाने के लिए यह अंकुश एक तरह से सही भी है। गौरतलब है कि कोई भी बैंक जनता के भरोसे पर ही चलता है। जमाकर्ता अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं और बैंक उस पैसे को ऋण के रूप में उन लोगों को देते है जिन्हें इसकी जरूरत होती है। इन ऋणों पर बैंक को ब्याज मिलता है और उसी ब्याज में से जमाकर्ताओं को उनकी जमाओं पर ब्याज मिलता है। सामान्यतः विश्वास के कारण लोग

सच यह है कि चाहे बैंक सरकारी हो या निजी, नियमों में सख्ती और सही निगरानी ही समाधान है। यह भी निश्चित है कि किसी भी संस्थान का मालिक सरकार है या निजी लोग, यह उसकी कुशलता का पैमाना नहीं हो सकता।
– स्वदेशी संवाद

अपनी अधिकांश जमा राशि को बैंक के पास ही रखते है, इसलिए बैंकों को सामान्यतः लिक्विडिटी का संकट नहीं आता। लेकिन बैंक पर जमाकर्ताओं का विश्वास जब डगमगाता है तो उन्हें लिक्विडिटी का संकट आ सकता है और जमा राशि वापिस न करने की स्थिति में बैंक फेल हो सकता है।

इसलिए जब रिजर्व बैंक ने जमा राशि की निकासी पर अंकुश लगाया है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि बैंक फेल हुआ है, बल्कि यह समझना चाहिए कि बैंक को फेल होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफी बड़ी मात्रा में बैंकों पर निर्भर करती है। भारत एक प्रबल बचत संस्कृति का देश है। गृहस्थ अपनी बचत को कई प्रकार से संग्रहित करते हैं, लेकिन बैंकों में जमा करना उसका सबसे लोकप्रिय तरीका है। गौरतलब है कि 31 मार्च 2019 तक निजी और सार्वजनिक बैंकों को मिलाकर कुल 126 लाख करोड़ रूपये बैंकों में जमा थे। चाहे बैंक छोटा हो या बड़ा, किसी भी हालत में उसका फेल होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यही कारण है कि यस बैंक के संकट में सरकार और रिजर्व बैंक ने तुरंत हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और उसके समाधान के उपाय शुरू हो चुके है। यस बैंक के बोर्ड का रिजर्व बैंक ने अधिग्रहण कर लिया है। स्टेट बैंक और एलआईसी को यस बैंक के शेयर खरीदने के लिए कहा गया है। कुछ सरकारी बैंकों के आला अधिकारियों को इस संकट से निपटने के लिए जिम्मेवारी दी गई है।

पिछले काफी समय से बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास बेहतर करने के लिए बैंकों में जमा राशि के बीमा की सीमा को पूर्व में एक लाख से बढ़ाने की कवायद चल रही थी। इसी वर्ष बजट में वित्तमंत्री ने इस बावत घोषणा की है कि इस बीमा राशि को बढ़ाकर पाच लाख किया जायेगा। रिजर्व बैंक ने भी यह कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और उनके हितों की सुरक्षा की जायेगी। यह भी कहा गया है कि बैंकों में जमा राशि पांच लाख रूपये तक पूर्णतया सुरक्षित है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रश्न है उनका तो पैसा डूबने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि उस पर भारत सरकार की गारंटी है।

यह पहली बार नहीं है कि रिजर्व बैंक ने किसी निजी बैंक को बचाने का प्रयास किया है, इससे पहले भी वर्ष 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के बोर्ड का भी रिजर्व बैंक ने अधिग्रहण कर लिया था।

सबक सीखने की दरकार

सरकार और रिजर्व बैंक के विभिन्न उपायों के कारण हालांकि हाल फिलहाल यस बैंक पर आया संकट टल जायेगा, लेकिन निजीकरण के इस युग में हमें इस संकट से सबक लेने की जरूरत है। लगातार बढ़ते एनपीए या यूं कहें कि डूबते ऋणों के चलते यस बैंक की आर्थिक हालत बद से बदतर होती गई। रिजर्व बैंक का कहना है कि उसके द्वारा बाजार आधारित समाधान के उसके उपाय सफल नहीं हुए, क्योंकि यस बैंक के प्रबंधन द्वारा विभिन्न प्रयासों के बावजूद अतिरिक्त पूंजी नहीं लुटाई जा सकी। इसलिए रिजर्व बैंक को मजबूरी में भारत सरकार की अनुमति से यस बैंक की जमाओं पर 30 दिन का यह अंकुश लगाना पड़ा और बोर्ड का पुनर्गठन करना पड़ा। इस संकट के पीछे रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रबंधन को ही दोषी ठहराया है।

लेकिन देखना होगा कि वर्तमान में निजी बैंकों में बढ़ते हुए डूबते ऋणों के पीछे रिजर्व बैंक भी कम जिम्मेवार नहीं है। जब सरकारी बैंकों एनपीए की समस्या से जूझ रहे थे, तब रिजर्व बैंक के तत्कालिक गवर्नर ने यह कहा था कि सरकारी बैंकों के प्रबंधन पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण सीमित है। जबकि निजी बैंकों पर रिजर्व बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकता है। लेकिन आज रिजर्व बैंक यस बैंक के प्रबंधन को ही उसके संकट का दोषी कह रहा है। वास्तव में निजी बैंकों के प्रबंधन दोष के लिए रिजर्व बैंक की वह नीति जिम्मेवार है जिसके अनुसार निजी बैंकों के प्रमोटरों पर यह शर्त लगाई गई कि वे एक निश्चित समय सीमा में इन बैंकों में अपनी अंशधारिता यानि मिल्कियत को शून्य करे। इसी क्रम में यस बैंक के मालिक राणा कपूर की अंशधारिता को क्रमशः घटाने के लिए मजबूर किया गया और आज स्थिति यह है कि यस बैंक के प्रबंधन में जो लोग है, उनकी कोई अंशधारिता बैंक में नहीं है। जो लोग यस बैंक का प्रबंधन चला रहे हैं उनका कोई स्टेक बैंक में नहीं है। यदि प्रमोटरों की अंशधारिता को शून्य नहीं किया गया होता तो बैंक के स्वास्थ्य में उनकी रूचि बनी रहती और बैंक इस हालत में नहीं पहुंचता। इसलिए अभी भी समय है कि रिजर्व बैंक प्रमोटरों की अंशधारिता को शून्य करने वाली उस नीति पर पुनः विचार करे।

निजीकरण नहीं है समाधान

पूर्व में रिजर्व बैंक के कुछ गवर्नर और अन्य आला अधिकारी सरकारी बैंकों के निजीकरण की वकालत करते रहे है। वे उस समय सरकारी बैंकों की खराब आर्थिक स्थिति के संदर्भ में यह कहा करते थे। लेकिन अब निजी बैंकों की बिगड़ती स्थिति और यहां तक कि बंद होने के कगार पर पहुंचने के कारण उनके इन सुझावों पर सवालिया निशान लग रहा है। सच यह है कि चाहे बैंक सरकारी हो या निजी, नियमों में सख्ती और सही निगरानी ही समाधान है। यह भी निश्चित है कि किसी भी संस्थान का मालिक सरकार है या निजी लोग, यह उसकी कुशलता का पैमाना नहीं हो सकता। ❑❑

उत्तर प्रदेश का बजट (2020–21)

युवाओं, किसानों व गरीबों पर केंद्रित

उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा 18 फरवरी 2020 को अपनी सरकार का चौथा ऐतिहासिक बजट पेश किया। जिसमें आय व प्राप्तियां 5,00,558.53 करोड़ रुपये तथा कुल व्यय 5,12,860.72 करोड़ रुपये अर्थात 12,302.19 करोड़ रुपये के घाटे को चिन्हित किया गया है। प्रदेश में गत वर्ष 4,79,701.10 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इसलिए वर्तमान बजट 2020–21 को अब तक का सबसे बढ़ा अर्थात 5.12860 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय का बजट है, जिसमें विशेषकर युवा व किसानों को बेहतर जीवन देने के लिए प्रयास किये गये है। इसके साथ साथ प्रदेश में उद्योग, पर्यटन व सांस्कृतिक परियोजनाओं को भी ध्यान दिया गया है। बजट में बुनियादी ढ़ांचा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देकर प्रदेश को आर्थिक रुप से संपन्न करने की कोशिश की गई है। अयोध्या व काशी के विकास की ऐसी योजनाऐं बनायी गई, जिनका लाभ सबको मिलेगा। बजट से मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ व वित्तमंत्री का आत्म विश्वास भी बढ़ा है क्योंकि बजट की सराहना प्रदेश के प्रत्येक समुदाय कर रहा है।

योगी सरकार ने युवा, किसान व गरीबों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। वर्ष 2022 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की बनाने के केन्द्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह बजट अपनी बड़ी भूमिका निभायेगा।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

विपक्ष आद्तन आलोचना कर रहा है जिसमें कोई विशेष दम नहीं है। विपक्ष बजट पर बहस के दौरान अपनी निराशा को परिभाषित करेगा। अब समय आ गया है कि विपक्ष को भी राज्य के विकास में अपना सक्रिय योगदान देते हुए विधानसभा व विधानपरिषद में सार्थक बहस करें तथा सकरात्मक सुधार की योजनाऐं बतायें। लोकतंत्र में विपक्ष की पारदर्शी व सकरात्मक आलोचना का विशेष महत्व होता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का मानना है कि केन्द्र की मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की सरकार बिना जाति व धर्म के भेदभाव के सभी के लिए काम कर रही है। समाज व राष्ट्र की सेवा करना किसी सौदे का माध्यम नहीं है। यह अपने अंतःकरण को सामने रखने का माध्यम है। हमने शासन की आदर्श व्यवस्था को रामराज माना है। जहां किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। हम ऐसे ही सेवा के भाव को विस्तार दे रहे है। योगी आदित्य नाथ ने कहा कि बटाईदार के लिए भी बीमा की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड़ तथा विंध्य क्षेत्रों में पानी की समस्या को समाप्त करने का प्रावधान हुआ है। निराश्रित गोवंश के भरण पोषण व गौ–आश्रम स्थल बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड़ ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900करोड़ रुपये तथा गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पंहुचाने के लक्ष्य

में प्रदेश का भी अभूतपूर्व योगदान होगा। बजट में अयोध्या पर्यटन और सांस्कृतिक योजनाओं के लिए 95 करोड़ रुपये, अयोध्या में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 500 करोड रुपये, तुलसी स्मारक भवन के नवीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये, गोरखपुर में रामगढ़ वाटर स्पोटर्स के लिए 25 करोड़ रुपये, हर जिले में युवा रोजगार के लिए युवा हब के माध्यम से नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए 50 करोड़, साइबर अपराध के नियंत्रण के लिए 3 करोड़ रुपये, केंसर संस्थान को 187 करोड रुपये, संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान को 820 करोड़ रुपये, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 292 करोड़ रुपये, अग्नि शमन विभाग को 10 करोड़, किसान दुर्घटना कल्याण बीमा के लिए 500 करोड़ रुपये, चिकित्सा व परिवार कल्याण के लिए 15,860.33 करोड़ रुपये के लिए, कृषि के लिए 6,176.27 करोड़ रुपये इत्यादि आंबटित किये गये है। कुल व्यय 5,12,860.72 करोड़ रुपये में से राजस्व खाते का 3,95,116.95 करोड़ रुपये तथा पूंजी खाते का 1,17,743.77 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया है।

युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाईयों में रोजगार में रहते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार वित्तीय वर्ष 2020–21 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को प्रारम्भ कर रही है। इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के युवाओं को उद्योग में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा। प्रदेश सरकार युवाओं को जो भत्ता देगी उसमें 1,500 रुपये प्रति मास की धन राशि केन्द्र सरकार तथा 1,000 रुपये प्रति मास की धनराशि राज्य सरकार के द्वारा तथा शेषधन राशि संबंधित उद्योग के द्वारा दी जायेगी। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान (युवा) के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल की जा रही है। प्रदेश में प्रत्येक जिले में युवा हब स्थापित होगा जो इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर एक वर्ष तक की परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा।

प्रदेश सरकार को आबकारी विभाग से 37,500 करोड़ रुपये, स्टाम्प और पंजीयन से 23,197करोड़ रुपये, वाहन कर से 8,650करोड़ रुपये, जीएसटी तथा वैट से 91,568 करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने बुनियादी ढ़ांचे के विकास और प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है।

रोजगार के लिए युवाओं की फौज को दक्ष व स्वावलंबी बनाने के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा की गई है। शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों और सुक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देते हुए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार के रोजगार से जोड़ा जायेगा।

बिजली, सड़कों, सेतुओं और सिंचाई के लिए 78,565.41 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। पांच एक्सप्रेस वे परियोजनाओं का संजाल बिछाने के लिए 5,060 करोड़ रुपये व्यय होंगे। मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित 637 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2,000 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों ओर इंड्स्ट्रियल कॉरिड़ोर की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये आंबटित हुए है।

ड़िफेंस कॉरिड़ोर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये आंबटित है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़ रुपये आंबटित हुए है। वर्ष 2020–21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641 लाख 74 हजार मीट्रिक टन और तिलहन का उत्पादन लक्ष्य 13 लाख 90 हजार मीट्रिक टन प्रस्तावित है। इसके लिऐ किसानों को 102 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। गांवों में मजदूरों की कमी को देखते हुए कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु 1,694 कस्टम हायरिंग केन्द्र और 305 फार्म मशीनरी बैंक खोलकर 40,606 उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण प्रस्तावित है।

इंड़ियन इंड़स्ट्रीज ऐसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार ने एक दैनिक अखबार को दी अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट में सुक्ष्म, लघु, एवम् मध्यम उद्यम के लिए कुछ विशेष नहीं है। ओडीओपी के लिए मात्र 250 करोड़ रुपये का प्रावधान है। हम आशा कर रहे थे कि औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुवधिाओं पर फोकस किया जायेगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

किसान कम पसीना बहाकर अधिक लाभ कमाये इस पर फोकस किया गया है। कृषि निर्यात बढ़ाने और राष्ट्रीय कृषि बाजार की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश की गई है। प्रदेश की सौ मंड़ी के आलावा 25 अन्य मंड़ियों को ई–नैम पोर्टल से जोड़ने की योजना है। कुल मिला कर प्रदेश की योगी सरकार ने युवा, किसान व गरीबों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। वर्ष 2022 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की बनाने के केन्द्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह बजट अपनी बड़ी भूमिका निभायेगा। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

बांधों न बांध हर ठांव बंधु!

जल प्रबंधन एवं बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बांधों के निर्माण को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और यह माना जा रहा है कि वर्षा के दिनों में बाढ़ के समय अपने आगोश में अपार जल राशि समेटे हुई नदियों को बांध बनाकर उन्हें सीमित करते हुए जहां एक और बाढ़ की समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर व्यवस्थित जल प्रबंधन भी सुचारू रूप से संभव हो सकता है, किंतु यह मानना बहुत युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता है। प्रारंभ में बड़ी–बड़ी नदियों पर बड़े बड़े बांथ बनाकर जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए खेतों पर पानी पहुंचा कर हरित क्रांति के सपने को साकार किया गया पर अब निरंतर पानी की मांग को देखते हुए बड़ी नदियों के साथ ही साथ छोटे–छोटे नदी नालों को भी बांधकर एक दायरे में सीमित करने का कार्य किया जा रहा है तथा उससे ग्रामीण स्तर पर तथाकथित छोटे छोटे बांधों का निर्माण कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है किंतु यह बांध जहां एक और अपेक्षित क्षेत्रफल को पूर्णरूपेण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं वहीं दूसरी ओर जनसंख्या एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के साथ ही साथ अनेकानेक समस्याओं को जन्म देकर मानव जीवन के समक्ष चुनौती बनकर खड़े हो रहे हैं।

आज आवश्यकता प्रकृति को चुनौती देने के स्थान पर प्रकृति का सहयोग प्राप्त कर उसके संरक्षण संवर्धन एवं प्रबंधन के अनुरूप आचरण कर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की है, जिससे न तो बाढ़ और भूकंप की भयंकरता का सामना करना पड़े और न ही प्राणियों के समक्ष पर्यावरण पारिस्थितिकी और जीवनयापन के आवश्यक तत्वों के अभाव का प्रश्न उपस्थित हो।

– **दिनेश प्रसाद मिश्र**

बांधों के निर्माण की घोषणा के साथ ही जनसामान्य के समक्ष अपने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। बांध छोटा हो या बड़ा, हर बांध अपने क्षेत्र में रह रहे निवासियों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे जमीन से उखड़े हुए लोग अपने जीवन को सुव्यवस्थित न कर पाने के कारण, संसाधनों के अभाव में इधर उधर भ्रमण करते हुए जीवन यापन हेतु पर्याप्त संसाधनों की खोज में प्रायः नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। एक और उनका आवास एवं जीवन की आधारभूत भूमि बांधों के पेट में समा जाती है वहीं दूसरी ओर सरकारें दिवा स्वप्न दिखाती हुई उन्हें मात्र लालीपॉप ही पकड़ाती हैं।

बाधों के निर्माण में आधारभूत तत्वों के रूप में जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना तथा बाढ़ पर नियंत्रण प्राप्त करना प्रमुख है। आज देश मे लगभग 5200 बड़े और मझोले बांध है जिनके द्वारा देश में खेतों खेतों की सिंचाई

तथा जल विद्युत उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। जहां तक खेतों की सिंचाई का प्रश्न है अब तक बनाए गए बांधों में से शायद ही कोई ऐसा बांध हो जो अपने लिए निर्धारित कृषि क्षेत्र की सिंचाई करने में सफल हुआ हो। नर्मदा नदी में बना सरदार सरोवर देश के सबसे बड़े बांधों में से एक है जिसकी क्षमता करीब 586 करोड़ क्यूबिक फिट है किंतु सरदार सरोवर से गुजरात के सौराष्ट्र में पानी न मिलने के कारण किसान नाराज हैं।

गत कुछ वर्षों में गुजरात सुरेंद्रनगर जिले सहित आसपास के निवासी किसानों पर नर्मदा बांदा से पानी चोरी करने का आरोप लगाते हुए 50 से अधिक स्थानों पर किसानों पर मामले दर्ज कराए गए हैं जिसे लेकर स्थिति इतनी बिगड़ गई है की गुजरात सरकार को कई स्थानों पर पानी की चोरी रोकने के लिए एसआरपी के जवान तक तैनात करने पड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय पानी प्रबंधन संस्थान के निदेशक तुषार साह का कहना है कि किसानों पर पानी की चोरी का केस बनाना बेबुनियाद है। जब किसान के खेत के पास पानी बह रहा हो और उसके खेत सूखे हो तो वह पानी लेगा ही। वस्तुतः सरकार परंपरागत जल संसाधनों को बचाने में नाकाम रही है। इसलिए सौराष्ट्र आज पीने के पानी और सिंचाई के लिए पूरी तरह नर्मदा पर निर्भर है, लेकिन अब तक सरकार लोगों से कह रही थी कि बांध की ऊंचाई न बढ़ने के कारण उन्हें पानी नहीं मिल रहा।

असलियत यह है कि सरकार नहरों का नेटवर्क ही नहीं बिछा पाई लेकिन अब ऊंचाई बढ़ने के बाद भी अगर पानी नहीं पहुंचा तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। बांध बंध जाने के बाद भी उनकी नहरों का जाल मानक के अनुसार नहीं फैल पाता। फलस्वरूप उनसे अपेक्षित सिंचाई का कार्य भी संपन्न नहीं हो पाता। एक रिपोर्ट के अनुसार कोई साढ़े चार सौ बांध निर्माणाधीन हैं, लेकिन इन निर्माणाधीन बांधों की वर्तमान स्थिति के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता।

देशभर के बांधों पर निगरानी का काम केंद्रीय जल आयोग करता है लेकिन निगरानी का यह काम सिर्फ 107 बांधों तक सीमित है, अन्य बांधों की स्थिति के संदर्भ में केंद्रीय जल आयोग भी मौन है। कोई नियंत्रक संस्था ना होने तथा किए जा रहे कार्य पर किसी प्रकार की निगरानी ना होने के कारण जहां धन का अत्यधिक अपव्यय होता है, वहीं दूसरी ओर योजनाओं की समय से पूर्ति ना हो पाने के कारण उनकी लागत भी निरंतर बढ़ती रहती है और बजट की मांग मुंह बाए खड़ी रहती है किंतु कार्य पूर्ण होने का नाम नहीं लेता।

वस्तुतः विकास के नाम पर बांधों के तटबंध, सड़क, नहर बनाकर और रेल लाइन आदि बिछाकर पानी के बहाव के मार्ग को बाधित कर दिया गया है।

आज देश में 5200 से अधिक बांध है जिनमें से सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 670 बांध ऐसे क्षेत्रों में ही स्थित है जो क्षेत्र भूकंप संभावित जोन की उच्चतम श्रेणी में आते हैं। इन बांधों की सुरक्षा के संदर्भ में क्या किया गया है। इनके निर्माण का स्तर क्या है तथा भूकंप की स्थिति में उनकी क्या स्थिति होगी? यह विशाल जल राशि से कैसी स्थिति उत्पन्न करेंगे, इस संदर्भ में किसी के भी द्वारा ना तो कुछ सोचा गया और ना ही कोई अध्ययन किया गया है।

वर्तमान समय में 300 से ज्यादा बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हो गए हैं। मोरबी बांध के ढह जाने के बाद भी हम सचेत नहीं हुए, बांध पर बांध बने जा रहे हैं। बिना यह सोचे कि अगर ऊपर वाला बांध टूट गया तो नीचे किस तरह की प्रलय आ जाएगी। वर्ष 1979 में गुजरात के भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित होकर मोरबी बांध के टूट जाने से वहां पर प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित हुआ था और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कम से कम 5000 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा पर बने कोसी नदी पर बने बांध को टूटे हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं जिससे प्रभावित होकर हजारों लोगों को बेघर होने के साथ अनेकलोगों को मौत का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2017 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के मलसीसर गांव में मलसीसर बांध के टूट जाने से अचानक ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ था।

बड़े बांधों के साथ ही छोटे–छोटे बांध भी निरंतर बनाए जा रहे हैं जिससे जलवायु पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी के समक्ष गंभीर चुनौती उपस्थित हो रही है। यह छोटे–छोटे बांध जहां एक और छोटी नदियों के

जल प्रवाह को बाधित कर उन्हें मृत प्राय ही नहीं बना देते अपितु उनके प्रवाह को समाप्त कर उनके जीवन को भी समाप्त कर देते हैं। सिंचाई के नाम पर ऐसे बांध जितने क्षेत्र को सिंचित कर पाते हैं उससे अधिक क्षेत्र को यह छोटी–छोटी नदियां अपने आप सिंचित करने के साथ अपने बाढ़ के समय छोड़ी गई मिट्टी से उर्वरा शक्ति प्रदान कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करते थे किंतु यह छोटे बांधों के बंध जाने से और छोटी नदियों का जीवन समाप्त हो जाने से उनके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर मछलियों के जीवन से लेकर जीव जंतु पशु पक्षी एवं मानव जीवन भी अनेक प्रकार से प्रभावित होता है तथा प्रकृति को अनपेक्षित हानि का सामना करना पड़ता है।

बांधों की सुरक्षा आज सबसे बड़ा प्रश्न है? जिसका उत्तर कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है। अगस्त2019 में बांधों की सुरक्षा समुचित निगरानी निरीक्षण और उनका संचालन सुनिश्चित करने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक पास किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि बांध एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है जिसका निर्माण सिंचाई विद्युत उत्पादन बाढ़ नियंत्रण पेयजल और औद्योगिक प्रयोजन के लिहाज से जल के बहुउद्देशीय उपयोगों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है कोई असुरक्षित बांध मानव जीवन पारिस्थितिकी एवं सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों के लिए खतरनाक हो सकता है ऐसे में बांध की सुरक्षा एक मुख्य चिंता का विषय है और यह राष्ट्रीय जिम्मेदारी है विधेयक में कहा गया है कि आपदाओं से संबंधित बांध से जुड़ी समस्याओं के निवारण और बांध सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए संबंधित नीति विकसित करने तथा आवश्यक नियमों की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन प्रस्तावित है जिसके द्वारा बांधों की ऊंचाई सहित अन्य मानक निर्धारित करते हैं बांधों की सुरक्षा हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाएंगे।

वस्तुतः बांधों की सुरक्षा एवं उनसे उत्पन्न खतरों एवं उनसे उत्पन्न दुष्प्रभावों को देखते हुए यह कहना है कि बांधों से होने वाले लाभ पर्याप्त प्राप्त कर लिए गए हैं, आज देश में जितने बांध बने हुए हैं उन बांधों से निरंतर लाभ प्राप्त होते रहेंगे, बांधों की सुरक्षा का प्रश्न अकाट्य प्रश्नचिन्ह की तरह सामने खड़ा है जिसका निदान अब तक खोजा नहीं जा सका है फलस्वरूप उनकी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुत हो गया बहुत बन गए बांध, बंद करो नित्य नए बांधों का बनाना, अब नए बांधों की आवश्यकता नहीं है।

पुराने बांधों को ही सुरक्षित रखाकर उनसे आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनके अन्य विकल्प तलाशे जाने चाहिए। मानव की तरह हर छोटे छोटे जीव जंतु एवं नदी नालों को अप्रतिहत गति से बहते हुए अपने जीवन, अपनी गति एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, जिसे छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है और यदि उन अधिकारों पर हस्तक्षेप करते हुए उनकी गति बाधित की जाती है तो उसके दुष्परिणाम परिलक्षित होंगे।

छोटे–छोटे जल स्रोतों एवं नदी नालों पर बन रहे बांधों से लेकर बड़ी–बड़ी नदियों पर बनने वाले बांधों की स्थितियों और उनके दुष्प्रभाव को देखकर लगता है कि अब नए–नए बांधों की आवश्यकता नहीं है पूर्व निर्मित जो बांध हैं,वह सुरक्षित रहें तथा उन्हीं का सदुपयोग होता रहे, यही पर्याप्त है। नए बांध बनाकर प्रकृति के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप करना एक प्रकार से उसे चुनौती देना है।

आज आवश्यकता प्रकृति को चुनौती देने के स्थान पर प्रकृति का सहयोग प्राप्त कर उसके संरक्षण संवर्धन एवं प्रबंधन के अनुरूप आचरण कर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की है, जिससे न तो बाढ़ और भूकंप की भयंकरता का सामना करना पड़े और न ही प्राणियों के समक्ष पर्यावरण पारिस्थितिकी और जीवन यापन के आवश्यक तत्वों के अभाव का प्रश्न उपस्थित हो। मनुष्य के साथ–साथ समस्त जीव–जंतुओं या यूं कहें प्राणी मात्र के जीवन के समक्ष चुनौतियां कम से कम है और ऐसी स्थिति बने कि जीवन सहज सरल रूप से संचालित होता रहे। ऐसी स्थिति में बांधों की स्थिति एवं उनके दुष्परिणाम को देखते हुए महाप्राण निराला की पंक्ति में कुछ परिवर्तन कर बस यही कहना है –बांधों न बांध हर ठांव बंधु, रोता है हर गांव बंधु। ❑❑

भारतीय वाङ्मय में पर्यावरण शिक्षा

भारतीय वाङ्मय में पर्यावरण शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे ऋषियों ने कहा–

सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत।।

सब सुखी हो, सब निरोगी हों, कोई दुःखी न हो, यह उद्देश्य केवल पर्यावरण शुद्धता से ही सम्भव हो सकता है।

वैदिक शांति मंत्र कहता हैः–

ऊँ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः,
सा मा शान्तिरेधि।। ऊं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।

इस शांति पाठ में पृथ्वी, अन्तरिक्ष, औषधी, हवा, जल, अग्नि, आकाश सभी को शांत रखने की इश्वर से प्रार्थना की गयी है। जिन पांच तत्वों – मिट्टी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश से मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि आदि का निर्माण हुआ है, उन सबको शांत रखने की अपेक्षा की गई है। हमारा गायत्री मंत्र भी **ऊं भू र्भुवः** से शुरू होता है – जो विश्व के कल्याण की कामना करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय वाङ्मय में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन को बहुत महत्व दिया गया है।

आधुनिक युग में पर्यावरण प्रदूषण एक भयावह समस्या है। देश में वनों का विनाश हो रहा है, वन्य प्राणी प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं फलस्वरूप पारिस्थितिक सन्तुलन बिगड़ रहा है हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के शिकार होते जा रहे हैं मानवता का विनाश हो रहा है, प्राकृतिक असन्तुलन का कारण हमारी बिगड़ती हुई मानसिकता है यदि यही स्थिति रही तो शीघ्र ही यह पृथ्वी वन एवं वन्य जीवों से विहीन हो जाएगी तथा मानव विनाश भी सम्भावी हो जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भारतीय जीवन दर्शन पर विचार करना आवश्यक है, हमारी संस्कृति पर्यावरण संवर्द्धन एवं संरक्षण वाली रही है, भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीना सिखाती है, वेद, मनु स्मृति, धर्मशास्त्र एवं उपनिषदों के नियम इस तारतम्य की इच्छा एवं आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं,

भारतीय संस्कृति ही हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना सिखाती है, आज की पर्यावरण प्रदूषण की भयावह समस्या का एकमात्र समाधान है कि भारतीय जीवन आदर्शो को मानते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना सीखे।
– **विजय वशिष्ठ**

वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद प्राचीनतम् है, जिसमें मुख्य रूप से प्रकृति को ही देवी मान कर स्तुति की गई है, वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को माता माना है, इसीलिए कहा **'माता भूमि अहं पुत्रोपृथ्वीया'।** भूमि ही प्रकृति का प्रथम तत्व है, पृथ्वी ही सम्पूर्ण भोगों की उत्पादकता है–इसीलिए इसे 'श्री' कहा गया है, वेदों में वृक्षों के महत्व का सर्वाधिक प्रतिपादन किया गया है, इसीलिए वृक्षो में देवता का निवास माना गया है तथा इनको न काटने पर बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में वट, पीपल, ऑवला, तुलसी आदि का पूजन करने का भी यही अभिप्राय है कि ये मानव जीवन की सुरक्षा करते हैं। हिन्दू धर्म में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाने की सलाह दी गई है, जिसका वैज्ञानिक कारण है तुलसी का पौधा ही संसार का एकमात्र पौधा जो दिन तथा रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ता है तथा उसकी पत्तियॉ प्रकाश संश्लेषण द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सोर ऊर्जा शोषित करती हैं, फलतः ऋषियों ने जनमानस में इस धारणा को बल दिया कि तुलसी में लक्ष्मी व विष्णु दोनों का निवास है,

वामन पुराण में तो प्रातः काल उठते ही पॉचो तत्वों का स्मरण करने की परम्परा पर जोर दिया गया है, पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपने बहाव, अग्नि अपने तेज, अन्तरिक्ष (आकाश) अपने शब्द, ध्वनि और वायु अपने स्पर्श गुण के साथ हमारे प्रातः काल को अपना आशीर्वाद दे, यही हमारी कामना है।

गीता में भगवान ने प्रकृति को अष्टकोणी बताया है पॉच तत्वों के अलावा मन, बुद्धि एवं अहंकार की भी गणना की गई है, ये पॉचो तत्व मिलकर मन और बुद्धि को निर्मल रखें तथा अहंकार को संयमित रखें, स्कन्ध पुराणा के अनुसार जिस घर में प्रति दिन तुलसी की पूजा होती है उसमें यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते (स्कन्ध पुराण 21.66)

वाराह पुराण (172.39) में तो पेड़ पौधो और वनस्पतियों के रोपण–पोषण और संवर्द्धन को पुण्य कार्य माना गया है, मन्त्र में व्यवस्था है कि जो व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक पीपल, एक नीम और एक बड़ (बरगद का वृक्ष) का पेड़ लगाएं, 10 फूलों वाले वृक्षों और लताओं का रोपण करें, अनार, नारंगी और आम के दो–दो वृक्ष लगाए, वह कभी नरक में नहीं जाता प्रकृति को धर्म से जोड़कर यह व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति प्रकृति का विनाश न करे,

भारतीय संस्कृति में जल को पवित्र तथा पुण्य माना है, जल ही प्राण है, सम्पूर्ण प्राणियों, वनस्पतियों तथा औषधियों में सार तत्व के रूप में जल ही विद्यमान है, अतः इसे परम रस कहा गया है, यह सभी प्राणियों में प्राण का संचार करने के कारण प्राण कहलाता है। ऋग्वेद में जल को दिव्य तत्व मानकर वरूण को उसका देवता माना गया है, ऋग्वेद में जल के उचित प्रयोग का विशेष निर्देश दिया गया है अन्यथा यह दुरूपयोग करने वाले का ही नाश कर देता है, वर्तमान में जल प्रदूषित होता जा रहा है, हमारी पवित्र गंगा मॉ प्रदूषित हो रही है इसी प्रदूषण को रोकने के लिए महाभारत में कहा गया है कि ''जल में 33 कोटि देवता रहते हैं, अतः इसमें मल–मूत्र त्याग सर्वथा वर्जित है, वर्तमान काल में भी जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल को दैवीय स्वरूप प्रदान कर उसकी शुद्धता यथावत् रखने का प्रयास करना चाहिए, वृक्ष लगाकर जल भण्डार की वृद्धि करनी चाहिए''

पर्यावरण की शुद्धता के लिए वेदों में यज्ञ का बहुत महत्व प्रतिपादित किया है, ऋषियों ने यज्ञ को धर्म से सम्बद्ध कर दिया। प्रकृति में होने वाले विकार की मात्रा को दृष्टिपथ में रखते हुए उन्होंने यज्ञ की मान्यताओं को भी निश्चित कर दिया– जैसे दैनिक, पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक, वार्षिक इत्यादि समय–समय पर आयोजित होने वाले इन यज्ञों से प्रकृति की शुद्धता, वर्षा की प्रचुरता, अन्न की उत्पत्ति इत्यादि कर्म व्यवस्थित होते रहते हैं। यज्ञ वातावरण के एक सीमित क्षेत्र को शुद्धा करते हैं, अर्थात् यज्ञ से उत्पन्न धुएं से नाइट्रोजन व अमोनिया उत्पन्न होकर वातारण की कार्बन डाइऑक्साइड को नष्ट करके वातावरण को शुद्धा करती है। घण्टानाद क्रिया के द्वारा उत्पन्न शब्द भी विषाणुओं का नाश करता है।

वर्तमान में व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का निदान यजुर्वेद के विधानों के अनुसार यज्ञ करने में है, पाश्चात्य विद्वानों ने भी यज्ञों के महत्व को स्वीकार है।

वायु एवं प्रदूषण का घनिष्ठ संबंध है, भारतीय मनीषियों ने कहा ''प्राण ही वायु है, वायु सभी जीवधारियों में प्रतिकारक तत्वों व अन्य पदार्थों का प्रेरक है, शतपथ में कथानक आता है कि सुष्टि के पूर्व सब और विद्यमान जल में वायु ने प्रवेश कर उसे आलोकित किया जिससे फेन की उत्पत्ति हुई तथा पुनःपुन आलोकित करने पर फेन से शिकता, शिकता से अश्मा (पत्थर) तथा अश्मा से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, वायु प्रदूषण है, आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है। बड़े शहरों में शुद्ध वायु की उपलब्धि बहुत बड़ी समस्या है।

भारतीय जीवन दर्शन में प्रकृति और संस्कृति को अलग–अलग करके देखना असम्भव–सा है। जहॉ तुलसी, वट एवं पीपल की पूजा, गाय का सम्मान, गंगा की स्तुति, सूर्य, चन्द्र, मरूत, जल और पृथ्वी में देवत्व की कल्पना की गई हो, वहॉ प्रकृति के अपमान की बात सोची भी नहीं जा सकती।

भारतीय, संस्कृति में अनेक पर्व एवं त्यौहार पर हम वन्य जीवों की पूजा अर्चना करते है, मोर सरस्वती के साथ, सिंह महाकाली के साथ, बैल शिव के साथ, हाथी इन्द्र के साथ, चूहा गणेश के साथ सदैव पूजनीय रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी बारह राशियों में से कई पशुओं के नाम पर है। भारतीय संस्कृति में वन्य प्राणियों का प्रमुख स्थान देकर प्रतिष्ठित ही नहीं किया, बल्कि समय–समय पर लोगों ने अपने प्राणो की आहुति देकर

वनों एवं वन्य प्राणियों की रक्षा भी की है। राजस्थान में ऐसे भी उदाहरण हैं जहॉ शासनादेश के बावजूद भी जनता ने एक भी पेड़ नहीं कटने दिया। जोधपुर जिले के गॉव खेजड़ली में 363 बलिदानियों ने स्वयं के प्राणों की आहुति देकर पेड़ो की रक्षा की ऐसा उदाहरण विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं।

भारतीय संस्कृति में प्रकृति के दोहन की छूट तो दी है, लेकिन उसके शोषण की नहीं वनों के विनाश को तो दण्डनीय अपराध माना है, स्कन्द पुराण के अनुसार ''सभी प्रकार के पेड़ों को काटना निन्दनीय है, यज्ञ आदि कारण के अलावा ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए। पदम पुराण में ''उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से नरक का अधिकारी माना है, जो जीव हिंसा करते हों या कुओं तालाबों और उद्यानों को प्रदूषित करते हों।

प्राणी मात्र की रक्षा एवं उसका कल्याण हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति का मूल मन्त्र है **''अहिंसा परमोधर्म''।** मनुस्मुति के अनुसार पशुओं की हत्या करने वाला केवल हिंसक नहीं कहलाता–जो व्यक्ति पशु हत्या की आज्ञा देता है, जो पशु को काटता है, जो उसे मारता है, जो मांस बेचता है या खरीदता है, जो उसे परोसता है एवं जो उसे खाता है–वे सब हत्या के दोषी हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हे दुष्टात्मा! यदि तुमने किसी पक्षी को भून कर खाया, तो समझ लो, तुम्हारे सारे यज्ञ, पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं और पवित्र नदियों में स्नान आदि व्यर्थ है, जैन ग्रन्थों में यही भावना प्रतिपादित की गई कि किसी भी प्राणी को मत मारो, यह धर्म का नित्य शाश्वत नियम है। जैन मत में केवल शारीरिक हिंसा ही वर्जित नहीं है, प्रत्युत वह बौद्धिक अहिंसा को भी अनिवार्य बताता है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में वन्य प्राणियों की हत्या को रोकने के लिए दण्ड की व्यवस्था की। उन्होनें लिखा कि ''अधिकारी को चाहिए कि वन उन सभी अपराधियों पर एक हजार पण (उस समय की मुद्रा का नाम) का दण्ड प्रतिरोपित करें जो राज्य द्वारा हत्या के लिए वर्जित हिरणों अथवा अन्य पशु–पक्षियों और मछलियों के शिकार के दोषी हों''।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति ही हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना सिखाती है, आज की पर्यावरण प्रदूषण की भयावह समस्या का एकमात्र समाधान है कि भारतीय जीवन आदर्शो को मानते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना सीखे।

आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारे शहर पर्यावरण प्रदूषण की भयंकर समस्या से ग्रस्त हैं। विश्व के 31 प्रदूषित शहरों में भारत के 20 शहर हैं। हमें शुद्ध हवा, पानी, अनाज, सब्जी–फल आदि उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण की भयावहता यू. एन. की एक रिपोर्ट से साफ होती है जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर के 10 लोगों में से 9 लोग जहरीली हवा लेने को मजबूर हैं। प्रतिवर्ष 70 लाख मौतें वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं – जिसमें सर्वाधिक संख्या भारत से है।

इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालयों से छात्रों को पर्यावरण शिक्षा तथा इसके संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए कार्य करने का संकल्प करावें। केवल सरकारी अभियान से यह कार्य नहीं हो सकता इसके लिए जन अभियान चलाना होगा। पेड़ लगाओ – पर्यावरण बचाओ, शिक्षा पाओ – पेड़ लगाओ, शादी रचाओ – पेड़ लगाओ, जन्मदिन मनाओ – पेड़ लगाओ, जैसे कार्यक्रम चलाकर पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जा सकता है। यह कार्य प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इसमें ज्ञान, तकनीक, धन आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल संकल्प लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। आओ हम सब मिलकर इस पृथ्वी को बचाएं तथा विश्व को यह संदेश दें कि भारतीय जीवन दर्शन एवं जीवन पद्धति से ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटा जा सकता है तथा इस पृथ्वी माता को बचाया जा सकता है। आओ हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करें। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

आर्थिक स्वतंत्रता के लिये जन-जागरण का आह्वानः दत्तोपंत ठेंगड़ी

22 नवम्बर 1991 स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के माध्यम से युद्ध की तैयारी का प्रारम्भ का दिन था। इसके पश्चात् 1 जनवरी, 1995 को भारत वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन यानि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। डब्ल्यूटीओ के सिंगापुर सम्मेलन में बार–बार यह घोषणा करने के बावजूद की– ''हम अमेरिका के सामने कभी घुटने नहीं टेंकेगे, उनके दबाव में नहीं आएँगे।'' किन्तु भारत सरकार ने संसद में प्रस्ताव रखे बिना, संसद की अनुमति लिये बिना जनता को अंधेरे में रखकर–सीधे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ले ली। तब से स्वदेशी जागरण मंच का प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में हम पूरी तरह गुलाम थे किन्तु उससे भी अधिक बुरी अवस्था में हम गुलाम हो जाएँगे। पाँच–छः साल की अवधि में हमारे सभी उद्योग, कृषि उनके हाथों में चली जाएँगे। हमारा सारा स्वातंत्र्य चला जायेगा। इन गोरे देशों के साधन सम्पन्न साम्राज्यवादी लोगों के खिलाफ, हम साधन विहिन होते हुए भी देशभक्ति के आधार पर लड़ सकते हैं। कई बार साधन व शक्ति होते हुए भी अंदरूनी मोर्चे पर ध्यान नहीं रहने से, हार का सामना करना पड़ता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान जयचंद की गद्दारी से हार गये। 23 जून 1757 की प्लासी की लड़ाई में बहुत अधिक सैन्य शक्ति वाला सिराजुद्दौला भी सेनापति मीरजाफर के भीतरघात से हार गया और क्लाइव जीत गया।

अब हमें युद्ध के दूसरे चरण में केवल मल्टीनेशनल, वर्ल्ड बैंक, आई.एम.एफ. आदि गोरे देशों की सरकारों के सामने कितने देशों की ताकत खड़ी कर सकते हैं, यह देखने के अलावा दूसरा मोर्चा जो इन ताकतों को आन्तरिक रूप से कमज़ोर कर सकता है वह भी संभालना पड़ेगा। इन समझौतों में होने वाली सांठ–गांठ में इन विरोधियों का साथ देने वाले, जिनको उन्होंने खरीदा है, उनके एजेन्ट देश में कौन हैं? बड़े उद्योगपति या बड़े नेता के रूप में काम

भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने इसके विरूद्ध आवाज उठाई यह आवाज इतनी प्रबल हुई कि जनमत जागरण हुआ जिसके दबाव के कारण वर्ष 2001 में दोहा (कतर) में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री परिषद की बैठक में भारत के मंत्री मुरासौली मारन अमेरिकी दबाव के आगे झुके नहीं और अमेरिका ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को वापस लौटा दिया।

– डॉ. रेखा भट्ट

कर रहे हैं उन्हें ठोस सबूत के आधार पर खोजना उसके बाद उनका हर तरह से आर्थिक व सामाजिक बहिष्कार करना। यदि ऐसे लोग सत्ता में है तो वे पुनः सत्ता में नहीं आ सके और डब्ल्यूटीओ की सदस्यता जैसे देशद्रोही निर्णय नहीं ले सकें। साधन सम्पन्न साम्राज्यवादी देशों का मुकाबला दक्षिण के नव स्वतंत्र देश साधन विहिन होते हुए भी एक साथ कर सकते हैं।

विदेशी पूंजी और विदेशी सरकारों के साथ हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था की सांठ–गांठ का विरोध करना बहुत कठिन हैं। वे बहुत बड़ी ताकत हैं उनकी तुलना में हम गरीब है, 'रावण रथी, विरथि रघुवीरा' इस तरह की स्थिति है। ऐसी असमान स्थिति में आमने सामने की मैदानी लड़ाई बहुत देर तक नहीं लड़ी जा सकती। स्वदेशी जागरण मंच ऐसे वैचारिक आन्दोलन का शंखनाद करता है। यह आर्थिक युद्ध हैं सभी संगठनों, शक्तियों की अपने–2 स्थान से लड़ाई चलाई जाए किन्तु एक उद्देश्य एक विचार और एक ध्येय के लिये परस्पर शिथिल सहयोग बना रहे। यदि इस मंच के वैचारिक आन्दोलन के माध्यम से हम देशभक्ति जागृत कर, जनशक्ति के आधार पर इन ताकतवर पूंजीपति महाशक्तियों से लड़ने का आव्हान् कर सकते हैं। जैसे देशभक्त वियतनाम लोगों की अमेरिका पर विजय हुई तो केवल सिद्धित्व के कारण हुई। वियतनाम जैसे छोटे देश ने अमेरिका के पास अस्त्र–शस्त्र के भण्डार और पैसे के गर्व को चकनाचूर कर दिया।

भारत देश में 1947 के संघर्ष के बाद अपनी ही केन्द्र सरकार के खिलाफ स्वतंत्र रूप से किन्तु संवैधानिक अहिंसात्मक मार्ग पर चल कर ही लड़ाई का रास्ता हड़ताल, धरना, रैली, हस्ताक्षर संग्रह, सत्याग्रह, आदि रूप में अपनाया जा सकता है। विदेशियों की आगे क्या नीति रहती है? उसे देखकर, ''होप फॉर दी बेस्ट एण्ड प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट'' यानि अच्छे से अच्छा घटने की आशा रखना किन्तु खराब से खराब घटना के लिये तैयार रहना' के आधार पर स्वदेशी जागरण मंच को कदम उठाने की आवश्यकता है।

भारत ने अभी तक कोई विरोध नहीं किया लेकिन विश्व के कई देशों में इन मल्टीनेशनल कम्पनियों के खिलाफ विद्रोह किये जा चुके हैं। यूरोपियन यूनियन (ई.यू.) के 12 देशों के साथ किसानों और खेती को लेकर उनकी सरकारों ने अमेरिका के साथ बड़ा एग्रीमेन्ट कर लिया। किन्तु जब इस एग्रीमेन्ट का क्रियान्वयन शुरू हुआ तो यूरोपियन देशों के किसानों ने विश्व इतिहास में पहली बार, आन्दोलन किया और सरकार ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये वह हस्ताक्षर वापस लेने की माँग रखी।

ऐसे ही दूसरा एग्रीमेन्ट था नाफ्टा (नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट) जिसमें मैक्सिको, कनाडा और उत्तरी अमेरिका शामिल थे। समझौते पर हस्ताक्षर पूर्ण गोपनीय रखे गये किन्तु क्रियान्वयन के समय जनता को पता चलने पर कनाडा में प्रचंड जन–जागरण हुआ। परिणामस्वरूप अगले चुनावों में जिस रूलिंग पार्टी ने समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, उनके सिर्फ दो सदस्य पार्लियामेन्ट में आ सके। जो नया प्रधानमंत्री बना उसने पहला पत्र युनाईटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति क्लिंटन को पत्र लिखा और कहा 'कनाडा डिमान्डस री–नेगोशियेशन ऑन ए एग्रीमेन्ट' यानि पहली बार किसी ने उस एग्रीमेन्ट पर फिर से नेगोशियेशन करने की माँग रखी। कनाडा में घोर असंतोष हुआ, मैक्सिको में किसान, हाथ में राइफल लेकर विद्रोह के लिये खड़े हो गये किन्तु सेना बुलाकर उनके विद्रोह को दबा दिया गया, कुचल दिया गया।

अमेरिका के मजदूरों और किसानों ने बहुत बड़ा विरोध किया जब उन्हें पता लगा कि 'नाफ्टा' एग्रीमेन्ट हम गरीबों के खिलाफ जाता है। सबसे बड़ा विरोध का स्वर ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष मिस्टर नादिर ने उठाया और अमेरिका सरकार के विरूद्ध अपने ही घर में अपने ही लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी।

इन देशों के लोगों को अपनी स्वतंत्रता व संप्रभुता पर होने वाले आर्थिक हमले के प्रति आगाह करना, सावधान करना जरूरी है। सभी विकासशील देशों को जो स्वदेशी की भावना से सहमत हों, चाहे वे डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्य हो या नहीं हो, उन्हें इकठ्ठा लाकर संगठित किया जाये और एक ऐसा गुट तैयार हो जो आर्थिक साम्राज्यवाद को रोकने और तेजी से होने वाले आर्थिक आक्रमण के लिये सावचेत करने के साथ युद्ध के लिये तैयार करने का कार्य भी करें।

'गेट' के समझौते के समय भारत से विकसित देशों के विरोध में मोर्चा खोलने और युद्ध में सभी विकासशील देशों का नेतृत्व करने के लिये आग्रह किया गया किन्तु भारत की सरकार उन देशों के द्वारा कर्ज के रूप में दिये गये सहयोग के कारण दबाव में थी अतः आर्थिक साम्राज्यवादी महाशक्तियों के विरोध में आगे आने से मना कर दिया। भारत के प्रतिनिधि डब्ल्यू.टी.ओ. में जाते हैं वहाँ यूरोप व अमेरिका के आगे झुक जाते हैं। ऐसे में विकासशील देशों को एक जुट करने और इनके शोषण के शडयंत्र के खिलाफ आवाज उठाई– मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कुआलालम्पुर में जी–15 कांफ्रेन्स में 15 विकासशील देशों ने स्वदेशी भावना जागृत करने की पहल की और प्रस्ताव पारित किया।

भारत सरकार ने 1945 से प्रारम्भ हुए आर्थिक साम्राज्यवाद के विरूद्ध कभी प्रतिकार नहीं किया। भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने इसके विरूद्ध आवाज उठाई यह आवाज इतनी प्रबल हुई कि

जनमत जागरण हुआ जिसके दबाव के कारण वर्ष 2001 में दोहा (कतर) में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री परिषद की बैठक में भारत के मंत्री मुरासौली मारन अमेरिकी दबाव के आगे झुके नहीं और अमेरिका ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को वापस लौटा दिया। सरकार के जागरण का दबाव अमेरिकी दबाव से अधिक प्रभावी रहा। सरकार की गलत नीतियों के विरूद्ध वही जागरण पूरे देश में, शहरों में गांवों में लाना है। देश की संप्रभुता खतरे में है, अपने देश की स्वतंत्रता को बचाये रखने के लिये जनमत का प्रचण्ड दबाव सरकार पर बनाना है, जिससे विदेशी महाशक्तियों के पक्ष में गलत नीति निर्धारित न की जायें और स्वदेशी के पक्ष में फैसले करें।

इसी तरह डेविसन एलबुग, आईएमएफ 'इण्टरनेशनल मॉनेटरी फण्ड' (आईएमएफ) के उच्चस्थ अधिकारी ने लिखा था कि ''मैनें आईएमएफ में रहते हुए इतना पाप कर्म किया है कि गरीब लोगों का खून मेरे हाथ पर है और दुनिया की सारी नदियाँ आकर भी मेरा हाथ साफ नहीं कर सकती। इस बात का मुझे पश्चाताप हो रहा है।''

महाथिर मोहम्मद ने 'साउथ कमीशन' नाम से एक समिति बनाई जिसके जनरल सेकेट्री थे मनमोहन सिंह। उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दी – 'चैलेंज टू दी साउथ' जिसमें उन्होंने बताया कि साउथ–साउथ कॉ–ऑपरेशन द्वारा गोरे देशों के दक्षिणी गैर गोरे देशों पर होने वाले आर्थिक आक्रमण को कैसे रोका जा सकता है।

सरकार में वित्त मंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने इसके एक भी सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा डब्ल्यूटीओ के माध्यम से अमेरिका यदि अपने हित में आर्थिक नीतियों को लागू करना चाहता है, और विकासशील देशों के अधिकारों की परवाह किये बगैर असमानता का व्यवहार करता है, विकासशील देशों की धमकी का डब्ल्यूटीओ पर कोई असर नहीं होता तो डब्ल्यूटीओ से बाहर आकर विकासशील देशों का दूसरा डब्ल्यूटीओ अलग खड़ा करेंगे और फिर हम सभी देश एकत्रित होकर आर्थिक साम्राज्यवादी देशों के साथ स्पर्धा में खड़े होंगे। स्वदेशी जागरण मंच का इस सन्दर्भ में नारा होगा ''WTO तोड़ों छोड़ों या मोड़ों''।

बाह्य शक्तियाँ कितनी ही प्रबल क्यों न दिखाई देती हो, उनका प्रतिकार करने की बीजभूत क्षमताएँ इस राष्ट्र में सनातन काल से रही है। स्वेदशी जागरण मंच ने संपूर्ण राष्ट्र का उचित ढंग से आह्वान करने की मानसिक क्षमता निर्मित कर दी है। हमारी सनातन सांस्कृतिक परम्परा के अनुसार संघर्ष शांत चित्त से करना चाहिये, किसी भी परिस्थिति में क्षुब्ध होने का प्रभाव हमारी निर्णय शक्ति पर पड़ता है। भगवान कृष्ण ने कहा है– 'युद्धस्व विगत ज्वरः'। अर्थात् सभी प्रकार के मानसिक ताप से मुक्त होकर युद्ध करो। सदैव इसी मानसिकता को दृढ़तापूर्वक स्थिर करते हुए स्वदेशी जागरण मंच अपनी रणनीति तय करेगा। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

स्वदेशी मतलब भारतीय कौशल, उद्यमिता को बढ़ावा: पीयूष गोयल

देश में विदेशी ई–कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भारतीय व्यापारी संघों की लामबंदी और स्वदेशी जागरण मंच की ओर से लगातार स्वदेशी को बढ़ावा देने के दबाव के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि स्वदेशी का मतलब आधुनिकता से परहेज नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो यह केवल भारतीय कौशल और उद्यमिता को मान्यता देने का विषय है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में करीब ऐसे सौ उत्पादों पर इंपोर्ट डयूटी को बढ़ाया गया है जिससे 9 बिलियन डॉलर का सामान भारत आता है। उन्होंने एचबीएल चेंज मेकर अवार्ड को संबोधित करते हुए कहा कि जिन उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है उसमें दैनिक जीवन से जुड़े कई उत्पाद है। इनमें जूता–चप्पल, फर्नीचर, ताला जैसे उत्पाद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगरबत्ती जैसे उत्पाद भी बड़ी संख्या में आयात किये जा रहे थे। जबकि यह हमारा परंपरागत उत्पाद है। लेकिन इसका लाभ विदेशी कंपनियों को हो रहा है।

दूसरी ओर, हमारे उत्पाद उनसे बेहतर, सस्ते और अच्छे हैं। इसी तरह से क्या हम खिलौना बनाकर भारत का आयात बिल कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से हम अपना कारोबार तो बढ़ा ही सकते हैं, इसके साथ ही लाखों नई नौकरी भी सृजित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि जब भी हम खरीदारी करें तो एक भारतीय होने के नाते यह एक बार जरूर सोचें कि क्या हम भारत में निर्मित वस्तु नहीं खरीद सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे पास कुशल कर्मचारी और उद्यमी है। हमारे पास तकनीक भी हैं। बस जरूरत है एक सही सोच की। इससे स्वदेशी और भारतीय उद्यमिता एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने चेंज मेकर अवार्ड जैसे कार्यक्रमों को एक बेहतरीन कदम करार देते हुए कहा कि इससे प्रतिभावान लोग आगे आएंगे। उनका विश्वास बढ़ेगा। उन्हें प्रतिष्ठा, मान्यता और पैसा मिलेगा। जिससे नए लोग भी कुछ नया करने के लिए आगे आएंगे।

https://www.lokmatnews.in/india/union-minister-piyush-goyal-swadeshi-jagran-manch-on-e-commerce-companies-says-swadeshi-does-not/

स्वदेशी जागरण मंच ने डेयरी उत्पादों के आयात का किया विरोध

अमरीकी डेयरी उत्पादों के आयात पर संघ द्वारा किये जा रहे विरोध के सुर में सुर मिलाते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने भी मोर्चा खोल दिया है। मंच ने अमरीकी गायों को मांसाहार खिलाये जाने को एक बड़ा मुद्दा मानते हुए कहा है कि भारत जैसे देश में अमरीका के दूध से बने उत्पादों के आयात की अनमुति देना हमारे किसानों के लिए तो चुनौती है ही, हमारी सनातन सांस्कृतिक भावना के विपरित भी है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक अश्वनी महाजन ने 'दि प्रिंट' को बताया कि हम गायों की पूजा करते हैं क्योंकि यह भारतीयों के लिए मां की तरह है। अमेरिका को यह समझने की जरूरत है कि यह (डेयरी आयात करना) एक अन्यायपूर्ण मांग है। मोदी सरकार भी इसी विचार को मानती है। पशु मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय कामधेनुयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया ने भी यही चिंता व्यक्त की है।

कथीरिया ने पूछा, 'सदियों से हमने गायों की पूजा की है। तो हम अमेरिका से अप्रमाणित डेयरी उत्पादों की अनुमति कैसे दे सकते हैं, चाहे वह मक्खन हो या पनीर या कोई अन्य उत्पाद हो? हमारी धार्मिक भावनाएं गाय के साथ जुड़ी हुई हैं। मोदी सरकार अमेरिकी डेयरी उत्पादों को प्रमाणीकरण के बिना कभी भी अनुमति नहीं देगी।'

स्वदेशी जागरण मंच का कहना है, 'भारत में दूध शाकाहारी भोजन का हिस्सा है। चूंकि अमेरिकी गायों को रक्त और मांस खिलाया जाता है, इसलिए भारत में ऐसी गायों के दूध का आयात प्रतिबंधित है। भारत चाहता है कि

अमेरिकी निर्यातक प्रमाणित करें कि दूध उन गायों का लिया गया है जिन्हें केवल शाकाहारी चारा दिया जाता है। अमेरिका को यह समझने की जरूरत है कि यह मांग केवल अन्यायपूर्ण नहीं है। इसमें धार्मिक कारणों से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह विचार अन्य भारतीय सरकारों ने भी रखा था।

भारत एक दशक से भी अधिक समय से यह दोहरा रहा है कि उसे उन मवेशियों के उत्पादों की आवश्यकता है जिन्हें शाकाहारी भोजन आजीवन खिलाया गया है। इस बीच, अमेरिकी डेयरी क्षेत्र ने इन आवश्यकताओं को 'वैज्ञानिक रूप से अनुचित' के रूप में भी वर्णित किया है।

भारत ने सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर धार्मिक भावनाओं के संरक्षण के अपने तर्क का समर्थन करने के लिए टैरिफ एंड ट्रेड (गैट) पर सामान्य समझौते के अनुच्छेद 20 (ए) का हवाला देते हुए अपनी स्थिति का बचाव किया है। यह अनुच्छेद प्रत्येक राष्ट्र को सार्वजनिक नैतिकता की अपनी परिभाषा देने और व्यापार और टैरिफ के संबंध में अपनी सांस्कृतिक संवेदनशीलता की रक्षा करने की अनुमति देता है।

भारत के रुख में कुछ वैज्ञानिक समर्थन हो सकता है। कुछ अध्ययनों से यह साबित होता है कि गायों को अपने भोजन में मांस योजक से बोवाइन स्पॉन्गिफॉर्म एन्सेफैलोपैथी (मैड काऊ बीमारी) जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के एक डेयरी विशेषज्ञ गुरु प्रसाद सिंह ने दिप्रिंट से कहा, 'इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि बोवाइन स्पॉन्गिफॉर्म एन्सेफैलोपैथी (बीएसई), जिसे पागल गाय की बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक घातक तंत्रिका रोग है। जिसे आमतौर पर पागल गाय की बीमारी के रूप में जाना जाता है, जो शांत जानवर में अपक्षयी परिवर्तन लाता है। उन्होंने कहा कि यह मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकता है।'

अमेरिका डेयरी उत्पादों का निर्यातक है। वैश्विक निर्यात में इसका हिस्सा 4.9 प्रतिशत रहा, जबकि 2018 में आयात का हिस्सा लगभग 2.8 प्रतिशत था। इस बीच, भारत में 2018 में वैश्विक डेयरी उत्पादों का निर्यात और आयात क्रमशः 0.3 प्रतिशत और 0.06 प्रतिशत रहा। हालांकि, अमेरिका और भारत के बीच डेयरी उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार की बात आती है तो भारत सरप्लस है।

https://hindi.theprint.in/india/rss-affiliated-swadeshi-jagran-manch-has-opposed-us-dairy-imports/118344/

स्वदेशी अपनाने से ही खत्म होगी देश में बेरोजगारीः सतीश कुमार

बांसवाड़ाः विद्यालय की वन्दना सभा में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख श्री सतीश कुमार एवं राजस्थान क्षेत्र सहसंयोजक श्री सतीश कुमार

आचार्य का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारम्भ मॉ भारती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन करके किया गया। पधारे अतिथियों का परिचय संस्थाप्रधान गोपालसिंह राव द्वारा किया गया। अतिथियों का तिलक, उपरणा एवं नारियल भेंट कर स्वागत विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य विनोद त्रिवेदी, ममता अधिकारी एवं परेश बुनकर द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में माननीय सतीश कुमार द्वारा भैया–बहिनों व आचार्यो को स्वदेशी भाव जागरण करते हुए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आह्वान किया। देश में रोजगार तभी बढ सकता है, जब हम हमारे देश में निर्मित वस्तुओं का उयोग करेगें और तभी हमारे लोगों का रोजगार मिलेगा। उक्त जानकारी प्रचार प्रसार प्रमुख दिव्यराज सिंह राजावत ने दी।

https://www.bhaskar.com/rajasthan/banswara/news/rajasthan-news-unemployment-will-end-in-the-country-only-by-adopting-swadeshi-satish-kumar-070007-6770857.html

गरीबी हटाने और स्वरोजगार बढ़ाने वाली नीतियां बनेंः कश्मीरी लाल

नीतियां ऐसी बनें, जिससे गरीबी दूर हो स्वरोजगार के अवसर बढ़े। स्वदेशी जागरण मंच का कार्य है कि स्वदेशी की ओर लोगों का मन आकर्षित किया जाए। मंच को इस बात के लिए गर्व है कि अनेक विदेशी कंपनियों के उत्पाद की ओर लोग आकर्षित नहीं हुए हैं। चीनी आयटम की खरीद फरोख्त भी कम हुई है। यह बड़ी सफलता है। उन्होंने

कहा कि हमारा यह भी उद्देश्य है कि जैविक खेती की ओर भी ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान दें।

होशंगाबाद रेलवे स्टेशन के पास होटल में हुई स्वदेशी जागरण मंच की क्षेत्रीय बैठक में राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने उक्त बात कही। उनके साथ ही मप्र और छत्तीसगढ़ के करीब दो दर्जन पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कश्मीरी लाल ने बताया कि यह स्वदेशी गंगा के नव भागीरथ दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म शताब्दी वर्ष है। जिसमें पूरे देश में अनेक कार्यक्रम और बैठकों का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच गांवों को प्राथमिकता देता है। यह सोच नहीं है कि शहर विकसित नहीं हो। उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि सबसे अच्छी प्रजाती की नीम हमारे देश में है। नीम की निबोली का पावडर काफी मंहगा मिलता है।

मंच के पदाधिकारी योगेश मोहन सेठा ने कहा कि इस अवसर पर बैठक में हरिद्वार और अन्य स्थानों पर जो पिछली बैठक में प्रस्ताव पास हुए थे उन विषयों पर कि तना कार्य हो सका है। इसकी समीक्षा की गई। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि आने वाले मई माह में अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी। इसके अलावा अमृतसर, पठानकोट आदि स्थानों पर भी मंच के कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि मंच के सभी पदाधिकारियों ने सभी साथियों और नागरिकों से अपील की है कि देश में बने उत्पादों की ही खरीदी की जाए। विदेशी वस्तुओं का बहिस्कार कि या जाए।

https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/hoshangabad-dhece-qh-fuhlu-ytih-jhtusdth-cztlu-jte-lergtk-clukand-fubehe-t-5408552

पहली बार 480 अरब डॉलर के पार पहुंचा देश का फॉरेक्स भंडार

देश का विदेशी पूंजी भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 28 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 5.42 अरब डॉलर की बड़ी बढ़ोतरी के साथ 481.54 अरब डॉलर के नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। यह लगातार 23वाँ सप्ताह है जब विदेशी पूंजी भंडार बढ़ा है। यह पहली बार 480 अरब डॉलर के पार पहुँचा है। इससे पहले 21 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी पूंजी का भंडार 2.90 करोड़ डॉलर बढ़कर 476.12 अरब डॉलर पर पहुंचा था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी पूंजी भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (एफसीए) में 4.37 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। इस उछाल के साथ विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 445.82 अरब डॉलर पर पहुँच गई। सप्ताह के दौरान आरबीआई ने सोने की खरीद जारी रखी, जिससे स्वर्ण भंडार 1.02 अरब डॉलर बढ़कर 3.68 अरब डॉलर का हो गया। आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित निधि 3.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 3.61 अरब डॉलर पर और विशेष आहरण अधिकार 50 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 1.43 अरब डॉलर हो गया।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-POLI-indian-forex-reserves-crossed-480-billion-dollars-for-the-first-time-126937795.html

कोरोना से ग्लोबल जीडीपी को लगेगा 347 अरब डॉलर का झटका

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा झटका लग सकता है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को 77 से 347 अरब डॉलर का नुकसान होगा।

एडीबी ने 6 मार्च 2020 को इस बारे में अपना विश्लेषण पेश किया है। इसमें कहा गया है कि वायरस की वजह से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को कई तरीकों से चोट पहुंचेगी। इनमें घरेलू मांग में भारी गिरावट, पर्यटन और कारोबार के लिए यात्रा में कमी, व्यापार और उत्पादन घटने, आपूर्ति बाधाएं और स्वास्थ्य प्रभाव शामिल हैं।

एडीबी ने कहा कि अर्थव्यवस्था कितना नुकसान पहुंचता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वायरस कितना फैलता है। हालांकि, इसको लेकर चीजें अभी अनिश्चित हैं। विश्लेषण के आधार पर एडीबी का आकलन है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को इससे 77 से 347 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचेगा। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 से 0.4 प्रतिशत होगा।

एडीबी ने कहा कि विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों और तीन महीने बाद यात्रा पर अंकुश में ढिलाई से हो सकता है कि यह प्रभाव कुछ कम रहे। ऐसी स्थिति में भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का नुकसान 156 अरब डॉलर रह सकता है। यह वैश्विक जीडीपी का 0.2 प्रतिशत होगा।

एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री यासुयुकी सवादा ने कहा कि चीन को इससे 103 अरब डॉलर यानी अपने जीडीपी का 0.8 प्रतिशत का नुकसान होगा। शेष विकासशील एशियाई देशों को 22 अरब डॉलर या जीडीपी का 0.2 प्रतिशत का नुकसान होगा। मनीला मुख्यालय वाले एशियाई विकास

बैंक ने फरवरी में जानलेवा वायरस से निपटने को एशियाई देशों को 40 लाख डॉलर की मदद की घोषणा की थी। दुनिया भर में इस वायरस से 3,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

https://www.livehindustan.com/business/story-global-gdp-may-lose-347-billion-dollar-due-to-corona-virus-asia-to-be-hit-significantly-says-adb-3071637.html

अंबानी को पछाड़ जैक मा बने एशियाई धन कुबेर

भारतीय उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के सिर से एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर का ताज छिन गया गया है। एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर अब चीन के उद्योगपति और अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड के संस्थापक जैक मा बन गए हैं।

तेल के दाम में आई भारी गिरावट के साथ–साथ वैश्विक बाजार में गिरावट के बाद भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की दौलत सोमवार को 5.8 अरब डॉलर घट गई, जिसके बाद वह एशिया के सबसे ज्यादा दौलतमंद लोगों की फेहरिस्त में दूसरे पायदान पर आ गए हैं।

इस फेहरिस्त में शीर्ष पर चीन के जैक मा आ गए हैं। मतलब, जैक मा अब एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर बन गए हैं, जिनकी दौलत 44.5 अरब डॉलर है, जोकि मुकेश अंबानी की दौलत से 2.6 अरब डॉलर से अधिक है।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, चीनी उद्योगपति जैक मा 44.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर बन गए हैं, जबकि भारत के मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

बता दें कि तेल की कीमतों को लेकर सउदी अरब और रूस के बीच छिड़ी जंग के कारण सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में 1991 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इससे आई गिरावट के कारण सोमवार को रिलायंस के शेयर में 12 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जोकि 2००9 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है।

https://www.livehindustan.com/business/story-jack-ma-of-alibaba-beats-asia-richest-person-defeating-mukesh-ambani-3077965.html

सेवा क्षेत्र के उत्पादन में 7 साल की सर्वाधिक तेजी

देश के सेवा क्षेत्र में फरवरी में लगातार पांचवें महीने तेजी दर्ज की गई। जारी मासिक सेवा पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआई) सर्वेक्षण के मुताबिक फरवरी में सेवा क्षेत्र में सात साल से अधिक की सर्वाधिक तेजी दर्ज की गई। सर्वेक्षण के मुताबिक नए ठेके और निर्यात की मांग में बढ़ोतरी और कारोबारी मनोबल सुधरने से सेवा क्षेत्र में भारी तेजी दर्ज की गई। आईएचएस मार्किट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जनवरी के 55.5 से बढ़कर फरवरी में 57. 5 पर पहुंच गया। जनवरी 2013 के बाद सेवा क्षेत्र के उत्पादन में यह सर्वाधिक तेजी है।

सेवा क्षेत्र की कंपनियों के नए ठेकों में फरवरी में अच्छी–खासी बढ़ोतरी हुई। यह सात साल से अधिक अवधि में दूसरी सर्वाधिक तेजी है। सर्वेक्षण के मुताबिक विदेश से मिलने वाले ठेकों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय मांग में बहुत अधिक तेजी तो नहीं आई, लेकिन इसकी रफ्तार लंबी अवधि के औसत से ज्यादा है। आईएचएस मार्किट की प्रधान अर्थशास्त्री पॉलियाना डी लीमा ने कहा कि पिछले साल सितंबर के बाद से हर महीने हर महीने सेवा क्षेत्र की रफ्तार में तेजी आई है। सितंबर में सेवा क्षेत्र में 19 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दिखी थी।

सेवा और मैन्यूफैक्चरिंग दोनों ही सेक्टरों की गतिविधियों को दर्शाने वाला कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स जनवरी के 56.3 से उछलकर फरवरी में 57.6 पर पहुंच गया। यह लंबी अवधि की औसत 54.6 की तुलना में अधिक है। लीमा ने कहा कि सेवा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी दोनों ही बाजारों से मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरवरी के आंकड़ों के मुताबिक सेवा और मैन्यूफैक्चरिंग दोनों ही क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ने से निजी क्षेत्र में आठ साल की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई।

आलोच्य महीने में रोजगार सृजन की रफ्तार हालांकि तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई। इसके अलावा फूड, लेबर, मटीरियल और तेल की कीमत में बढ़ोतरी की खबरों के बीच सेवा क्षेत्र की कंपनियों की इनपुट लागत में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-POLI-service-sector-production-growth-fastest-7-years-126905150.html

क्रिप्टोकरेंसी से हटा बैन, बिटकॉइन से कर सकेंगे लेनदेन

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन, जस्टिस आर रवींद्र भट्ट, जस्टिस वी सुब्रह्मण्यन की पीठ ने क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बैन को हटा दिया है। ऐसे में अब ग्राहक देश के सभी बैंक में इससे लेनदेन कर सकेंगे। आरबीआई की ओर से बिटकॉइन जैसी कई क्रिप्टोकरेंसी पर साल 2018 में प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और कुछ संस्थान इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आरबीआई के सर्कुलर को चुनौती देने के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आईएएमएआई ने 2018 के आरबीआई सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टोकरेंसी में व्यवसाय न करने के लिए निर्देश जारी किया था। आईएएमएआई ने अपने तर्क में दावा किया कि आरबीआई के कदम ने वर्चुअल करेंसी (टबे) के माध्यम से वैध व्यावसायिक गतिविधि पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने 6 अप्रैल, 2018 को एक सर्कुलर से निर्देश जारी किया था कि इसके द्वारा विनियमित सभी इकाईयां वर्चुअल करेंसी में सौदा नहीं करेंगी या किसी व्यक्ति या इकाई को इससे संबंधित सेवाएं प्रदान नहीं करेंगी।

क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिद्म पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है, जिसका कोई मालिक नहीं होता। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। इस करेंसी में कूटलेखन तकनीक का प्रयोग होता है। इस तकनीक के जरिए करेंसी के ट्रांजेक्शन का पूरा लेखा–जोखा होता है, जिससे इसे हैक करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि क्रिप्टोकरेंसी में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम होती है। बता दें कि इंटरनेट पर इस वर्चुअल करेंसी की शुरुआत जनवरी 2009 में बिटकॉइन के नाम से हुई थी।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-BANK-sc-allows-cryptocurrency-trading-cancels-rbis-2018-circular-126905043.html

बीएसएनएल को 39000 करोड़ रुपये का घाटा

सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल का घाटा बीते वर्ष 2019 में अप्रैल–दिसंबर की अवधि में 2.5 गुना बढ़कर 39,089 करोड़ रुपये हो गया। पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड को पटरी पर लाने के लिए काम करने की बात सरकार कह चुकी है। बहरहाल, संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने संसद में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस दूरसंचार कंपनी को पिछले वित्तवर्ष 2018–19 में 14,904 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

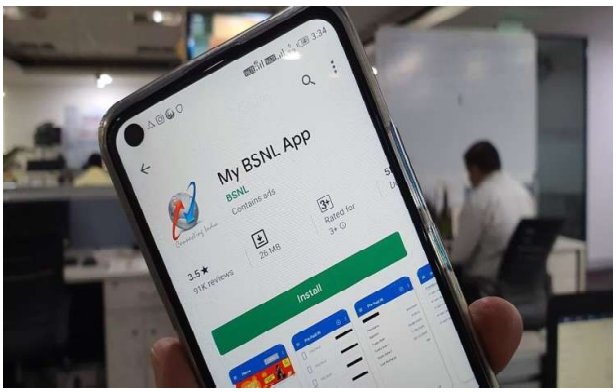

धोत्रे ने राज्यसभा में गुरुवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल से जानकारी मिली है कि चालू वित्तवर्ष यानी वर्ष 2019–20 (31 दिसंबर, 2019 तक) में उसका संचित घाटा 39,089 करोड़ रुपये है। बता दें कि सरकार ने पिछले साल 23 अक्तूबर को फोर–जी स्पेक्ट्रम आवंटन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) सहित घाटे में चलने वाले बीएसएनएल और एमटीएनएल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए 68,751 करोड़ रुपये का पैकेज दिया था। ❑❑

https://www.amarujala.com/india-news/bsnl-loss-in-apr-dec-2019-widens-over-2-point-5-times-to-rs-39000-cr-psu-company

दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्मशताब्दी वर्ष (2019–20)

सचित्र झलकियां

कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

पुरी, उड़ीसा

बागपत, उत्तर प्रदेश

भीलवाड़ा, राजस्थान

चित्तौड़गढ़, राजस्थान

दिल्ली

स्वदेशी पत्रिका
डाक तिथि 15–16 मार्च 2020 नई दिल्ली पी.एस.ओ.
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2018-19-20
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्मशताब्दी वर्ष (2019–2020)

सचित्र झलकियां

केरल

बाड़मेर, राजस्थान

ग्वालियर, मध्य प्रदेश

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती